सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 30, नई दिल्ली । शुक्रवार, 12 अप्रैल 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे।

03 कार चालक ने बाइक सवार युवती को मारी टक्कर, फिर उसे 100 मीटर तक घसीटा
06 थोपे गए चुनावों पर रायशुमारी
08 निरस्त रहेगी सिंगरौली, सत्याग्रह और जननायक एक्सप्रेस...

परिवहन विशेष द्वारा चलाए जा रहे अभियान : सड़क सुरक्षा, जाम मुक्त सड़के, हादसे मुक्त सड़के, महिला सुरक्षा, प्रदुषण नियंत्रण और आपदा निवारण सेवा के लिए

परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के साथ सहयोगी कुछ संस्थाओं का संक्षिप्त परिचय जाने और अन्य सहयोगी संस्थाओ का परिचय कल के प्रकाशन में

भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (पंजीकृत)

वर्ष 2020 में इस राष्ट्रीय संगठन को पंजीकृत करवाया गया था और हमारा कार्य ट्रक मालिको व ट्रांसपोर्टो की समस्याओ को लेकर भारत एवम् समस्त राज्य सरकारों तक पहुंचा कर बातचीत के माध्यम से हल करवाना है, भारत देश के सभी राज्यों/ जिलो में हमारी संस्था के कार्यालय और पद्दाधिकारी ट्रक मालिको के हितो की रक्षा के लिए कार्यरत हैं। हमारी मुख्य भूमिका किसी भी एक प्रदेश के सदस्य की दुसरे प्रदेश मे कोई समस्या हो उस प्रदेश की कमेटी द्वारा उसको हल करना व सहयोग करना सर्वोपरी है। हमारी संस्था का राष्ट्रीय कार्यालय CW 194, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली 110042 हैं जहां पर कोई भी ट्रक चालक/ मालिक/ आपरेटर अपनी समस्या के समाधान के लिए आ सकता हैं। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीएस नागरा स्वयं यहां समस्याओं के समाधान करवाने हेतु उपस्थित रहते हैं। 09212029151 पर कोई भी ट्रक चालक/ मालिक किसी भी राज्य से सीधा सम्पर्क कर अपनी समस्या से अवगत करा कर हल पा सकते हैं।

दिल्ली में बहोत सी गैर सरकारी सँस्थायें समाज सेवा का कार्य कर रहीं हैं। लाईफ सेवर फाउंडेशन ट्रस्ट जोकि दिल्ली से त्रस्त एक्ट में रजिस्टर्ड है। यह संस्था जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि मानव जीवन की रक्षा के लिये कार्य करती है। युवाओं को अचानक घायल व्यक्ति का जीवन कैसे बचाया जाये उसका प्रशिक्षण देकर जिसमे सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा (फ़र्स्ट ऐड), एडवांस ट्रेनिग फॉर सी पी आर, एंड आवश्यकता होने पर फ़र्स्ट एड पोस्ट लगाकर नागरिकों की दवाई पट्टी करके सेवा करना। अधिक जानकारी हेतु श्रीमती मोनिका ट्रस्टी - 8383045984 दानी सज्जन भी संपर्क करें आपके द्वारा दी गई राशी से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकेंगे। संस्था को एक एम्बुलेंस की सख्त आवश्यकता है दानी सज्जन क्रप्या सम्पर्क करें।

दिल्ली में बहोत सी गैर सरकारी सँस्थायें समाज सेवा का कार्य कर रहीं हैं। उन्हीं में युथ बेस डवलपमेंट सोसाइटी जोकि दिल्ली से रजिस्टर्ड है। युवाओं के भविष्य को संवारने के लिये कार्य कर रही हैं । संस्था की ओर से समय समय पर स्वास्थ्य व जीवन रक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। जिनमे युवाओं को आपातकालीन स्तिथि के दौरान किसी घायल या ह्रदय आघात के समय रोगी के जीवन की रक्षा कैसे की जाये। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये महिला शसक्तीकरण के तहत स्वयं सहायता गुरुप के माध्यम से सिलाई कढ़ाई / कोई खाने योग्य प्रोडक्ट बनाकर सेल करना, एवं योग्यता अनुसार कम्प्यूटर प्रशिक्षण, या अन्य कोई ऐसा प्रशिक्षण जिससे उनको आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिले। अधिक जानकारी के लिये श्री योगेश कुमार प्रेजिडेंट युथ बेस डवलपमेंट सोसायटी दिल्ली 9818724806, दानी सज्जन क्रप्या सम्पर्क करें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सक्षम बनाने में सहयोग कर सकें आपके सहयोग के बिना असम्भव है।

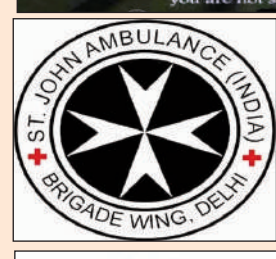

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन (आई-एफईवीए)

भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने भारत के लिए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है - नेट-शून्य हासिल करना। इस विशाल कार्य को प्राप्त करने के लिए हरित (इलेक्ट्रिक) गतिशीलता महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने एक श्रृंखला ली है। इसे प्राप्त करने के लिए उत्पादक और प्रगतिशील नीतिगत उपाय। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन, विकास और नीति वकालत के लिए एक एसोसिएशन है। 2019 से निवेश, वकालत, व्यापार नेटवर्किंग, प्रौद्योगिकी विनिमय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि के लिए सेमिनार/सम्मेलन आयोजित करने के लिए विदेशी मिशनों और सरकारों की सहायता (साझेदारी) कर रहा है। i-FEVA नीति निर्माण, निवेश और व्यापार के अनुकूल वातावरण और व्यापार विकास का समर्थन करता है। नेटवर्किंग, वकालत, परामर्श और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्योग, नीति निर्माताओं, शिक्षा जगत, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच तालमेल बनाकर। जापान, कोरिया, मलेशिया, दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में अपने सचिवालय और क्षेत्रीय समितियों के साथ, IFEVA विभिन्न क्षेत्रों पर मजबूती से काम करता है। हमारे पास EV उद्योग में 1000 से अधिक सदस्य हैं (2w, 3w, बैटरी सप्लायर, Ev चार्जर, BLDC मोटर, अपशिष्ट प्रबंधन), i-FEVA के साथ लाभ

1. व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म अन्य ईवी और एक्सेसरीज कंपनी के साथ आसानी से बातचीत करने के लिए
2. ईवी उद्योग ओईएम, राज्य और केंद्र सरकारों के साथ भौतिक बातचीत के लिए मंच।
3. वैश्विक व्यापार और राजनीतिक नेताओं से ऑनलाइन और ऑफलाइन मुलाकात करने का मंच।
4. ईवी सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन।
5. विदेशी ओईएम सहयोग
6. विदेशी OEMs के साथ प्रौद्योगिकी और ज्ञान साझा करना
7. भारतीय और वैश्विक कॉर्पोरेट दिग्गजों के साथ नेटवर्किंग के अवसर।
8. ईवी व्यवसाय को बढ़ाने और नए ईवी बाजार और अवसर विकसित करने के लिए साझा मंच।
9. नीति, रणनीति, योजना, कार्यान्वयन और उद्योग प्रतिक्रिया के लिए सरकार का समर्थन करें।
10. आयात निर्यात पर विशेष प्रशिक्षण
11. आपके आयोजनों के लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रचार
12. 50 वर्ष से अधिक अनुभव वाली विशेषज्ञों की टीम के साथ जीएसटी एवं आयकर मार्गदर्शन
13. हमारे समाचार पत्र पर प्रतिदिन निःशुल्क समाचार पत्र संपादकीय
14. दुनिया भर में अपने आयोजनों की ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार
15. एएसडीसी द्वारा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का समर्थन
16. आपके उत्पादों के प्रकार परीक्षण और अंशांकन के लिए समर्थन और मार्गदर्शन
17. विपणन के लिए सहायता
18. सूचीबद्ध बैंकों के माध्यम से बैंकिंग, वित्त, बीमा
19. रिकॉर्डेंट द्वारा ऑटोमेशन सॉफ़्टवेयर के साथ भुगतान पुनर्प्राप्ति समर्थन
20. अधिवक्ताओं की विशेषज्ञ टीम के साथ कानूनी सहायता।
21. सदस्य निर्देशिका
22. स्टार्ट-अप सहायता/ मार्गदर्शन/ परियोजना सहायता/ औद्योगिक प्रशिक्षण / इंटर्नशिप/ प्लेसमेंट सहायता
23. महिला उद्यमियों को उनके कौशल को बढ़ाने में सहायता करें
24 पूरे भारत और विदेशों में रोजगार सृजन सहायता
25. तकनीकी वक्ताओं/पैनलिस्ट/उद्योग विषय विशेषज्ञों/विशेष कार्य बलों के लिए सहायता।

हम वर्तमान और भविष्य की योजना और दीर्घकालिक व्यक्तिगत/व्यावसायिक संबंधों को एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए क्रॉस टेबल चर्चा या ऑनलाइन बैठकों के लिए तैयार हैं।

1. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल एसोसिएशन
2. परीक्षण उपकरण इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (टीआईआईसीआई)

पता दिल्ली: तीसरी मंजिल, एमबी1, मास्टर ब्लॉक, शकरपुर पूर्वी दिल्ली-110092
www.fevaev.com,

"कनीना स्कूल बस दर्दनाक हादसा: एक अविस्मरणीय घटना" :- ओमनी फाउंडेशन एवं टोलवा

परिवहन विशेष न्यूज

महेंद्रगढ़। महेंद्र गढ़ में त्रासदी, **जब सरकारी छुट्टी होने के बावजूद स्कूल खोलकर प्रबंधक द्वारा स्कूली बच्चों को स्कूल बुलाया गया** कनीना से एक स्कूल बस एक विनाशकारी दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके परिणामस्वरूप कई युवाओं की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना ने समुदाय को सदमे में डाल दिया है, जिससे स्कूल बस सुरक्षा के बारे में नए सिरे से चिंताएं पैदा हो गई हैं और भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए कड़े नियमों की आवश्यकता भी।

यह दुर्घटना छात्र परिवहन में संवर्धित सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता की गंभीर याद दिलाती है। स्कूल आने-जाने के दौरान छात्रों की भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मौजूद, मौजूदा कानूनों और विनियमों के बावजूद, यह दुखद घटना इन उपायों के अधिक कठोर प्रवर्तन और कार्यान्वयन की अनिवार्यता को रेखांकित करती है।

इस हृदय विदारक घटना के मद्देनजर, अधिकारी स्कूल बस दुर्घटनाओं के मूल कारणों का पता लगाने और सुरक्षा प्रोटोकॉल बढ़ाने के प्रयास तेज कर रहे हैं। सड़क और परिवहन संबंधित एजेंसियों के सहयोग से, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को निर्धारित करने और सुरक्षा नियमों के पालन में किसी भी चूक की पहचान करने के लिए गहन जांच कर रहा है।

हालाँकि दुर्घटना का सटीक कारण अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि सुरक्षा दिशानिर्देशों के संभावित उल्लंघन और अपर्याप्त निगरानी सहित कारकों के संयोजन से यह बढ़ गया है। यह गंभीर वास्तविकता स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त पालन के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डालती है, जिसमें वाहनों का उचित रखरखाव, गति सीमा का पालन और बोर्ड पर प्रशिक्षित परिचारकों की उपस्थिति शामिल है।

इस त्रासदी के जवाब में, हितधारक भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की वकालत कर रहे हैं।

मुख्य सिफारिशों में सभी स्कूल बसों में जीपीएस ट्रैकिंग और सीसीटीवी निगरानी प्रणाली जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाओं की स्थापना के साथ-साथ चालक आचरण और वाहन रखरखाव के संबंध में सख्त दिशानिर्देश लागू करना शामिल है।

इसके अलावा, छात्रों, अभिभावकों और स्कूल अधिकारियों के बीच सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अधिक सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता पहल की आवश्यकता पर आम सहमति बढ़ रही है। छात्रों की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देकर, हम ऐसी बेतुकी त्रासदियों को रोकने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्कूल आने-जाने की हर यात्रा सुरक्षित हो।

चूंकि समुदाय निर्दोष लोगों की जान जाने पर शोक मनाता है और इस विनाशकारी घटना से प्रभावित लोगों के समर्थन में एकजुट होकर रैलियां निकालता है, इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने दुख को सार्थक कार्रवाई में बदलें। निरंतर वकालत, सुरक्षा नियमों के कठोर प्रवर्तन और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से, हम उन लोगों की स्मृति का सम्मान कर सकते हैं जिन्हें हमने खो दिया है और एक ऐसे भविष्य की ओर प्रयास कर सकते हैं जहां इस तरह की त्रासदियों को अतीत में छोड़ दिया जाएगा। **रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन**

सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी भिवानी में आज प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं। प्रशासन को पता होते हुए भी कोई कदम नहीं उठाया जाता। नाबालिग़ बच्चे स्कूटी व मोटरसाइकल्स से स्कूल आते हैं। स्कूल, अभिभावक व प्रशासन को सब दिखता है परंतु कोई कुछ नहीं कहता। महँगी फ़ीस हैं सामान्य स्कूलों की भी। वहीं अधिकतर स्कूलों की एक ही दुकान से ड्रेस मिलेगी, एक ही दुकान से पुस्तकें मिलेंगी। छुट्टी होने पर भीड़ का ये आलम होता है की आधा पौना घंटा ट्रैफ़िक में खड़े रहना एक बहुत ही सामान्य बात है। भिवानी में हाल ये है की बच्चे अपने वाहन दुकानों व दफतरों के सामने खड़े कर के चले जाते है और फिर दोपहर तक दुकान पर आने वाले ग्राहक परेशान होते है जिससे की व्यापारी के काम पर सीधा असर पड़ता है। चौक पर चालान काटे जाते हैं परंतु स्कूल में वाहनों पर आ रहे नाबालिग बच्चों का इलाज ना स्कूल के पास है और ना ही प्रशासन के पास। आज महेंद्रगढ़ में हुई घटना में हम सब बराबर के ही दोषी है जो की सड़क पर चलती इस भेड़ चाल को रोज़ देखते हैं परंतु आवाज़ नहीं उठाते। घायलों के शीघ्र ठीक होने की प्रार्थना व ईश्वर उन नन्हे मुन्नो की आत्मा को शांति दे व परिवार को इस त्रासदी को सहने की ताक़त दे। ओम्-शांति शांति शांति।

@माधव वशिष्ठ।

हादसे के बाद जागा प्रशासन

महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे पर बड़ी कार्रवाई, RTA के सहायक सचिव निलंबित; स्कूल संचालक और प्रिंसिपल हिरासत में

महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। महेंद्रगढ़ के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के सहायक सचिव प्रदीप कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने बस ड्राइवर धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही स्कूल संचालक होशियार सिंह और प्रिंसिपल दीप्ति को हिरासत में लिया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

परिवहन विशेष न्यूज

महेंद्रगढ़। नारनौल में कनीना के गांव उन्हाणी के पास आज एक दर्दनाक बस हादसे में छह स्कूली बच्चों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। महेंद्रगढ़ के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के सहायक सचिव प्रदीप कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

वहीं पुलिस ने बस ड्राइवर धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया। इसमें उसके शराब पीने की पुष्टि हुई है। वहीं इस मामले में स्कूल संचालक होशियार सिंह और प्रिंसिपल दीप्ति को हिरासत में लिया गया है।

संचालक और प्राचार्य के खिलाफ एफआईआर

वहीं घटना पर शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके अलावा सभी स्कूल संचालकों से स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा। उन्होंने कहा कि इस घटना में जिम्मेदार बस चालक, स्कूल संचालक व प्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं स्कूल की मान्यता भी रद्द की जाएगी।

कारण बताओ नोटिस जारी किया गया

सीमा त्रिखा ने कहा कि राष्ट्रीय अवकाश के दिन स्कूल खोलने पर जीएल पब्लिक स्कूल प्रबंधक को मान्यता रद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हादसे का शिकार हुई स्कूल बस का 2018 के बाद का प्रदूषण सहित फिटनेस नहीं है। अब स्कूल प्रबंधक शपथ पत्र देंगे। स्कूल प्रबंधक स्कूल चलाएं लेकिन जिम्मेदारी से निभाएं।

शराब का सेवन नहीं करने को लेकर शपथ पत्र

उन्होंने कहा कि वाहन तय मापदंड के अनुसार हैं या नहीं हैं। यह भी अब सभी स्कूल प्रबंधक शपथ पत्र के माध्यम से जिलाशिक्षाधिकारी को सुनिश्चित कराएंगे। स्कूल प्रबंधक शपथ पत्र देंगे कि मां सरस्वति के मंदिर में काम करने के समय शराब का सेवन नहीं करेंगे। अभिभावक बच्चों को आंख बंद करके बस में बैठाते हैं। बस स्कूल प्रबंधक की मानी जाएगी, ठेकेदार की नहीं मानी जाएगी।

घटना में जान गंवानेवालों की हुई पहचान

1. वंश (14 वर्ष), पिता- दुष्यंत
2. रिकी (13 वर्ष), पिता- रविंद्र
3. अंशु (17 वर्ष), पिता- संदीप कुमार
4. याक्षु (14 वर्ष), पिता- संदीप कुमार
5. युवराज (15 वर्ष), पिता- संजय
6. सत्यम शर्मा (17 वर्ष), पिता- राकेश शर्मा

मोटर वाहन नियम के अंर्तगत क्या परिवहन विभाग राष्ट्रीय, राजकीय स्तर, यातायात पुलिस और पुलिस का काम सिर्फ राजस्व के लिए चालान करना है और कुछ नहीं?

ओमनी फाउंडेशन एवं टोलवा

यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है और भारत सरकार एवम् राज्य परिवहन विभाग इसमें फेल हो चुका है, सिर्फ कानून पर कानून बनते जा रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में भी इसका जिक्र है लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो है इसके लिए भारत सरकार को सभी राज्य के परिवहन विभाग के आयुक्तों की भी ड्यूटी लगानी आवश्यक हो गई है ऐसे हादसो, दुर्घटनाओं और गैर कानूनी तरीके से चलने वाले वाहनों के लिए इन पर भी कार्यवाही करनी होगी तभी इस समस्या का हल होगा, वरना पूरे देश में हर चौराहे पर गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं यह सभी वाहन चलाने वाले सरकार का टैक्स चोरी करते रहेंगे। सीसीटीवी की निगरानी होते हुए भी पूरे देश के अंदर यह चोरी निरंतर जारी है इसके लिए प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय को कार्रवाई करनी होगी अगर इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन नियम का कोई ओचित्य ही नहीं रहेगा। देश के सभी राज्यों में प्रवर्तन शाखा को मोटर व्हीकल एक्ट 2019 कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए जिससे गैर कानूनी तरीके से यह सभी कर चोरी ना कर सके। पूरे देश में स्कूल एवं कॉलेज के मालिकों को भी चिंतन मंथन करना होगा और परिवहन विभाग के आला अधिकारियों के साथ मिलकर इसका समाधान निकालना होगा कि हम आने वाला समय कैसे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कर सकती है। यह पूरे देश का महत्वपूर्ण मुद्दा है इसका हल भी हम सभी को मिलकर करना होगा। **इसके लिए तीन डिपार्मेंट जिम्मेदार हैं परिवहन विभाग राष्ट्रीय एवम् राजकीय स्तर, यातायात पुलिस और पुलिस**

जाने देवी माँ के 3 बड़े मंदिर , जहां मां को चढ़ाई जाती है शराब

राजस्थान में कई ऐसे बड़े मंदिर हैं, जहां से लोगों धार्मिक भावनाएं बेहद अलग अंदाज के साथ जुड़ी हुई हैं। आस्था के प्रतीक इन मंदिरों की ऐसी मान्यताएं हैं कि इन मंदिरों में जाकर मन्नत मांगने से हर मुराद पूरी होती है। प्रदेश के कुछ देवी मंदिर ऐसे भी हैं जहां शराब का भोग लगता है। यानी देवी मां को प्रसाद के रूप में शराब चढाई जाती है। देवी मां शराब का प्रसाद पाकर प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मन्नतें पूरी करती हैं। चैत्र नवरात्रि के मौके पर जानते राजस्थान के कुछ ऐसे देवीय मंदिरों के बारे में, जिनकी पहचान निराली है।

> टोंक से 40 किलोमीटर दूर दूणी गांव में दुणजा माता का मंदिर है। टोंक से देवली रोड पर 20 किलोमीटर आगे चलने पर नेशनल हाईवे से 20 किलोमीटर अंदर दूनी गांव है। वहां पर देवी मां का मंदिर है जो अपने आप में विशेष ख्याति लिए हुए है।

आमेर का शीला माता मंदिर

जयपुर शहर के पास आमेर किला परिसर में शीला माता का मंदिर है। यहां देवी दुर्गा की पूजा काली माता के रूप में की जाती है। कहा जाता है कि जयपुर के राजा मानसिंह जब केदार से हार गए थे तब उन्होंने काली देवी से जीत की प्रार्थना की थी। रात को उनके सपने में देवी मां प्रकट हुई और जीत का वरदान दिया। राजा मानसिंह की मुराद पूरी हुई तो उन्होंने अपने महल में ही माता रानी का मंदिर स्थापित कर दिया। इस मंदिर में शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। नवरात्रि के दौरान माता के इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है।

नागौर का भुवाल माता मंदिर

राजस्थान के नागौर जिले में मेड़ता के पास भुवाल माता का मंदिर है। देवी दुर्गा के इस मंदिर में भी शराब का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी भक्त जब अपनी आंखें बंद करके मां की प्रतिमा के समक्ष प्रसाद के रूप में शराब का प्याला आगे करता है तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर शराब को स्वीकार कर लेती है और शराब का प्याला तुरंत ही खाली हो जाता है। बची हुई शराब को वहां स्थित भैरव मंदिर में चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भुवाल माता के मंदिर का निर्माण डाकुओं ने करवाया था। बताया जाता है कि वहां एक पेड़ के नीचे देवी मां स्वयं प्रकट हुई थी जिसके बाद डाकुओं ने देवी मां के मंदिर का निर्माण कराया। नवरात्रि के दौरान सैंकड़ों किलोमीटर दूर से भक्त देवी मां के दर्शन करने आते हैं।

दूणी गांव में दुणजा माता का मंदिर

टोंक से 40 किलोमीटर दूर दूणी गांव में दुणजा माता का मंदिर है। टोंक से देवली रोड पर 20 किलोमीटर आगे चलने पर नेशनल हाईवे से 20 किलोमीटर अंदर दूनी गांव है। वहां पर देवी मां का मंदिर है जो अपने आप में विशेष ख्याति लिए हुए है। यहां देवी मां को शराब का भोग लगाया जाता है। यह मंदिर करीब 900 साल पुराना है। कहा जाता है कि यहां देवी मां पाषाण के रूप में स्वयं प्रकट हुई थी। कुछ साल पहले तक खुले में शराब का भोग लगाया जाता था लेकिन कुछ वर्षों शराब के भोग के दौरान पुजारी की ओर से पर्दा लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी मां भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करती है।

सिरदर्द को 5 मिनट में ठीक करने वाली प्राकृतिक चिकित्सा

नाक के दो हिस्से हैं दायाँ स्वर और बायां स्वर जिससे हम सांस लेते और छोड़ते हैं ,पर यह बिल्कुल अलग - अलग असर डालते हैं और आप फर्क महसूस कर सकते हैं। दाहिना नासिका छिद्र ₹सूर्य₹ और बायां नासिका छिद्र 'चन्द्र' के लक्षण को दर्शाता है या प्रतिनिधित्व करता है।

सरदर्द के दौरान, दाहिने नासिका छिद्र को बंद करें और बाएं से सांस लें और बस ! पांच मिनट में आपका सरदर्द 'गायब' है ना आसान ?? और यकीन मानिए यह उतना ही प्रभावकारी भी है।

अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं तो बस इसका उल्टा करें यानि बायीं नासिका छिद्र को बंद करें और दायें से सांस लें, और बस ! थोड़ी ही देर में ₹तरोताजा₹ महसूस करें।

दाहिना नासिका छिद्र 'गर्म प्रकृति' रखता है और बायां 'ठंडी प्रकृति'

अधिकांश महिलाएं बाएं और पुरुष दाहिने नासिका छिद्र से सांस लेते हैं और तदन रूप क्रमशः ठन्डे और गर्म प्रकृति के होते हैं सूर्य और चन्द्रमा की तरह।

प्रातः काल में उठते समय अगर आप बायीं नासिका छिद्र से सांस लेने में बेहतर महसूस कर रहे हैं तो आपको थकान जैसा महसूस होगा ,तो बस बायीं नासिका छिद्र को बंद करें, दायीं से सांस लेने का प्रयास करें और तरोताजा हो जाएँ।

अगर आप प्रायः सरदर्द से परेशान रहते हैं तो इसे आजमायें ,दाहिने को बंद कर बायीं नासिका छिद्र से सांस लें बस इसे नियमित रूप से एक महिना करें और स्वास्थ्य लाभ लें।

बस इन्हें आजमाइए और बिना दवाओं के स्वस्थ महसूस करें।

पेट की गर्मी से छुटकारा दिलाने में ये चीज है बहुत है फायदेमंद

गर्मी बढने से लोगों को सेहत से जुड़ी कई तकलीफ हो रही हैं। खासकर, ज़्यादा गर्मी और धूप की वजह से लोग गैस, अपच, खट्टी डकार, पेट फूलना, पेट या फिर सीने में जलन से परेशान हैं। दरअसल, गर्मी के मौसम में खराब लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से भी पेट से जुड़ी कई परेशानियां सामने आती हैं। ऐसे में स्वस्थ्य शरीर के लिए आपके पेट का सेहतमन्द रहना बहुत जरूरी है। आपके पेट के लिए किचन में पाया जानेवाला अजवाइन मसाला बेहद लाभदायक है। अजवाइन के अर्क में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो पाचन में सुधार करती है और कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करती है। दरअसल, अजवाइन वाइन पाचन, गैस जैसी समस्याओं में ही असरदार नहीं है बल्कि आपके पेट को भी ठंडा रखता है। अजवाइन में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटी-इंफ्लेमेट्री गुण के अलावा और भी बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं किन-किन तरीकों से अजवाइन का सेवन किया जा सकता है। अजवाइन पेट की गर्मी सहित कई बीमारियों को दूर करने में बेहद कारगर है। इसके नियमित सेवन से पेट फूलने, बदहजमी और गैस जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। गर्मियों के मौसम में लोगों को फैंस और एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो अजवाइन को खाएं। अजवाइन में मौजूद तत्व एसिडिटी से आराम दिलाने में आपकी मदद करते हैं। इन दिनों लोग बढ़ते मोटापे से बेहद परेशान हैं, वजन बढ़ने से लोग कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। ऐसे में अपने वजन को कम करने के लिए आप अजवाइन के पानी का सेवन करें। इसका पानी आपके कमजोर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिससे वजन आसानी से कम होता है। अजवाइन का पानी बनाने के लिए आप अजवाइन के बीज को रातभर भिगोकर रखें और सुबह एक गिलास में इसे गर्म करें और फिर इस पानी को आप छानकर पी लें। स्वाद के लिए आप इसमें शहद मिलाएं।

इस हैल्थी ड्रिंक पीने से बढ़ती है इम्यूनिटी , शुगर ब्लड प्रेशर भी रहता है कंट्रोल ,जाने क्या है ?

नारियल पानी जिसे एक हेल्दी ड्रिंक के तौर पर पिया जाता है.जिसमे पोशाक तत्व भरपूर मात्रा में पाएं जाते हैं. इसे अगर आप रोजाना पीते है तो इसके कई फायदे आपको अपने स्वास्थ्य में देखने को मिलने लगते हैं. नारियल पानी में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स नेचुरल सोर्स पाए जाते हैं. इसे रोज पीने से शरीर में पानी की कमी पूरी होती है. इसे रोजाना पीने से आपके शरीर पर इसके कई फायदे होने लगते हैं तो चलिए जानते हैं नारियल पानी पीने के फायदे.

क्या होता है नारियल पानी पीने का फायदा ?

नारियल पानी में 94% पानी और बहुत कम फैट होता है. इसमें मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं. एक कप नारियल पानी का मतलब लगभग 240 मिलीलीटर में 60 कैलोरी का होना. नारियल पानी पीने का एक और लाभ यह है कि यह मैग्नीशियम का एक अच्छा सोर्स है. यह इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकता है और टाइप टू डायबिटीज के बेहतर रिकवरी में मदद कर सकता है. वहीं अगर आप इसे रोजाना पीते हैं तो बीपी भी कंट्रोल में रहता है.

नारियल पानी पीने के अन्य फायदे

इम्यूनिटी बढ़ता है अगर आप रोजाना नारियल पानी का सेवन करते हैं तो इससे कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं और यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है. **सिरदर्द से बचाता है** तेज धूप और गर्मी की वजह से कई बार आपको डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो सकती है और अचानक से तेज सिर दर्द भी हो सकता है ऐसे में अगर आप तुरंत नारियल पानी पियेंगे तो आपके शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, जिससे पानी की कमी कंट्रोल हो जाएगी और आपकी सर दर्द की समस्या दूर हो जाएगी. **तनाव मुक्त रहते हैं** काम का बोझ और बिजी शेड्यूल के वजह से आपके ऊपर तनाव हावी हो जाता है.जिससे छुटकारा पाने के लिए नारियल पानी का सेवन करें। यह मेटाबॉलिज्म में सुधार का तनाव को दूर करने में मदद करता है. **थकान नही होती** नारियल पानी में कैलोरी कम और पोषक तत्व ज्यादा पाए जाते हैं. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर में होने वाले थकान को महसूस नहीं होने देता. रोजाना सुबह नारियल पानी पीने से थकान और कमजोरी दूर हो जाती है. इससे आपको इंस्टैंट एनर्जी भी मिलती है।

गर्मी के मौसम में चिरौंजी खाना है बेहद फायदेमंद

गर्मी में खानपान की वजह से पेट की समस्याएं सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। ऐसे में अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं तो डाइट में चिरौंजी जरूर शामिल कर लें। खीर का स्वाद बढ़ाने वाले चिरौंजी के छोटे से दाने पेट को स्वस्थ बनाने में मददगार साबित होते हैं। चिरौंजी तासीर में ठंडी होती है जिसे गर्मी में खाने से कई फायदे मिलते हैं। चिरौंजी खाने का तरीका आयुर्वेद के अनुसार एक दिन में आपको 3-5 ग्राम से ज्यादा चिरौंजी के बीज नहीं खाने चाहिए। एक बार में ज्यादा चिरौंजी खाने की बजाय रोज सीमित मात्रा में इसका सेवन करें। आप दूध में उबालकर या फिर दही में मिक्स करके, खीर में डालकर चिरौंजी खा सकते हैं। फलों के साथ भी चिरौंजी का सेवन किया जा सकता है।

चिरौंजी खाने के फायदे पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करे। चिरौंजी के छोटे से दाने एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होते हैं। इन्हें खाने से पाचन संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। चिरौंजी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पाचनक्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। इससे गैस और अपच की समस्या कम होती है। चिरोंजी में प्रोटीन और विटामिन्स पाए जाते हैं जो आमाशय के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। कब्ज की समस्या में राहत कब्ज की समस्या से परेशान रहने वालों को डाइट में चिरौंजी जरूर शामिल करनी चाहिए। इससे काफी फायदा होगा। चिरौंजी के बीज फुल फाइबर का सोर्स हैं। इससे आंतों को हेल्दी बनाने में मदद मिलती है और कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। पाचन सुधारक चिरौंजी के बीज को पेट में अपचन की समस्या होने पर सेवन कर सकते हैं। इससे पाचन में सुधार आता है और शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में मदद मिलती है। चिरौंजी के बीज डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जो पाचन सुधारक के रूप में काम करते हैं। पेट को रखे ठंडा चिरौंजी ऐसा मेवा है जिसकी तासीर ठंडी होती है। गर्मी के दिनों में इसे आसानी से खा सकते हैं। पेट के ठंडा रखने के लिए चिरौंजी जरूर खाएं। इससे गर्मी में होने वाली पेट से जुड़ी समस्याओं को कम किया जा सकता है।

समस्त बृजमंडल की जानकारी...

ब्रज के १२ कुंज हैं। पुष्पा कुंज, फल कुंज, रस कुंज, मधु कुंज, गो कुंज, द्वार कुंज, नवकुंज, शशिकुंज, प्रेम कुंज, शिद्धव कुंज, लक्ष्मी कुंज, तुलसी कुंज।

ब्रज के सात सागर हैं। ध्रुव सागर, गोपाल सागर, कनक सागर, गोप सागर, बैकुंठ सागर, लक्ष्मी सागर, क्षीरसागर।

ब्रज के १२ अधिवन हैं। परमबृस्म मथुरा, राधाबल्लभ राधाकुंड, यशोदानंदन नंदगांव, नवल किशोर दानगढ़, ब्रज किशोर ललित ग्राम, राधाकृष्ण वृषभानपुर, गोकुलेंद्र गोकुल, कामधेनु बलदेव, गोवर्धन नाथजी गोवर्धन, ब्रजवट जाववट, युगल किशोर वृंदावन, राधारमण संकेतवन।

ब्रज के 40 बिहारीजी । अजन बिहारी, अंकुर बिहारी, अप्सरा, ऊद्धव, कोकिला, कुंजबिहारी, किलोल, गोविंद, चिंताहरण, चंद्र, चतुर, तुष्णावर्त, दानबिहारी, दावानल, पूतना, नवलबिहारी, प्रेमबिहारी, पिता बिहारी, बांकेबिहारी, बकुल बिहारी, ब्रस्मांड बिहारी, प्रेम बिहारी, वृस्मांड बिहारी, बिछुल बिहारी, मथरोड़ बिहारी, मानबिहारी, मोर बिहारी, रासबिहारी, रसिक बिहारी, रमण बिहारी, ललित बिहारी, ब्रज बिहारी, बन बिहारी, बुद्ध बिहारी, वेदबिहारी, संकेत बिहारी, शाक बिहारी, श्री बिहारी, श्रृंगार बिहारी, सत्यनारायण बिहारी, शांतनु बिहारी।

ब्रज के पांच पर्वत हैं। चरण पहाड़ी (कामवन), चरण पहाड़ी (कामर), नंदगांव (शिव), बरसाना (बृस्म,) गोवर्धन (विष्णु)।

ब्रज के सात कदमखंडी हैं। गोविंद स्वामीजी, पिसावा, सुनहरा, करहला, गांठौली, ऊद्धवक्यारी, दौऊ मिलन की।

ब्रज के हिंडोला। श्री कुंड, करहला, संकेत, आजनोखर, रासौली, गहवरवन, वृंदावन, शेषशायी।

ब्रज के प्रमुख सरोवर हैं। सूरज सरोवर, कुसुम सरोवर, विमल सरोवर, चंद्र सरोवर, रूप सरोवर, पान सरोवर, मान सरोवर, प्रेम सरोवर, नारायण सरोवर, नयन सरोवर।

ब्रज की सोलह देवी हैं कात्यायनी देवी, शीतला देवी, संकेत देवी, दंदिहारी, सरस्वती देवी, वृंदादेवी, वनदेवी, विमला देवी, पोतरा देवी, नरी सैमरी देवी,
सांचौली देवी, नौवारी देवी,
चौवारी देवी, मथुरा देवी।

ब्रज यात्रा में आनंद आए तो बोलिये. ₹ राधेकृष्ण राधेकृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधेश्याम राधेश्याम श्याम श्याम राधे राधे ।।₹

500 साल बाद रामनवमी पर होगा 'श्री राम' का सूर्य तिलक, होगा अद्भुत नजारा, गर्भगृह में 'सूर्य' की किरणें कैसे पहुंचेंगी ? डिटेल में जानिए

हिंदू नववर्ष 'विक्रम संवत 2081' की शुरुआत के साथ अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामनवमी पर्व को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां भी चल रही हैं। एक ओर जहां इसी साल नव्य-भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वहीं अब राम मंदिर में विज्ञान का चमत्कार भी रामनवमी को देखने को मिलेगा, जिसमें प्राकृतिक रचना और मानवीय संरचना का अनूठा संगम होगा। चैत्र नवरात्र की नवमी को रामनवमी महापर्व होता है, जिसके उत्सव के लिए इस बार राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला के नूतन विग्रह पर सूर्य की किरणों से तिलक होगा। राम मंदिर की स्थापना और उद्घाटन के बाद यह पहली बार होगा। सूर्य तिलक के लिए विज्ञान की मदद ली गई है। क्या है प्रोजेक्ट सूर्य तिलक ट्रस्ट ने इसकी सूर्य तिलक के प्रबंधन व संयोजन का दायित्व रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को सौंपा है। इस आयोजन को प्रोजेक्ट 'सूर्य तिलक' का नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने एक पद्धति विकसित की, जिसमें मिरर, लेंस व पीतल का प्रयोग हुआ है। इसके संचालन के लिए बिजली या बैटरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक वर्ष रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक होगा ।रामनवमी के दिन मध्य बेला में 12 बजे रामलला का ढाई से पांच मिनट तक सूर्य की किरणों से अभिषेक होगा। इस अवधि में सूर्य की किरणें सीधे रामलला के ललाट पर आपतित (गिरेंगी) होंगी। रश्मियों से मुख मंडल भी आलोकित होगा। इसी समय राम जन्मोत्सव का उल्लास भी प्रस्फुटित होगा। सोमवार को इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। मंदिर की व्यवस्था से जुड़े विहिप नेता गोपाल ने परीक्षण की सफलता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार को भी इसका परीक्षण हुआ था, जिसमें सफलता प्राप्त हुई। ट्रस्ट ने की थी प्रोजेक्ट की परिकल्पना जानकारों का मानना है कि दुनिया में बहुत ही कम मंदिर ऐसे हैं, जहां भगवान की मूर्ति पर सूर्य किरण से तिलक होता हो। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में राम मंदिर को भव्यातिभव्य बनाने के लिए श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी परिकल्पना बहुत पहले कर ली थी।

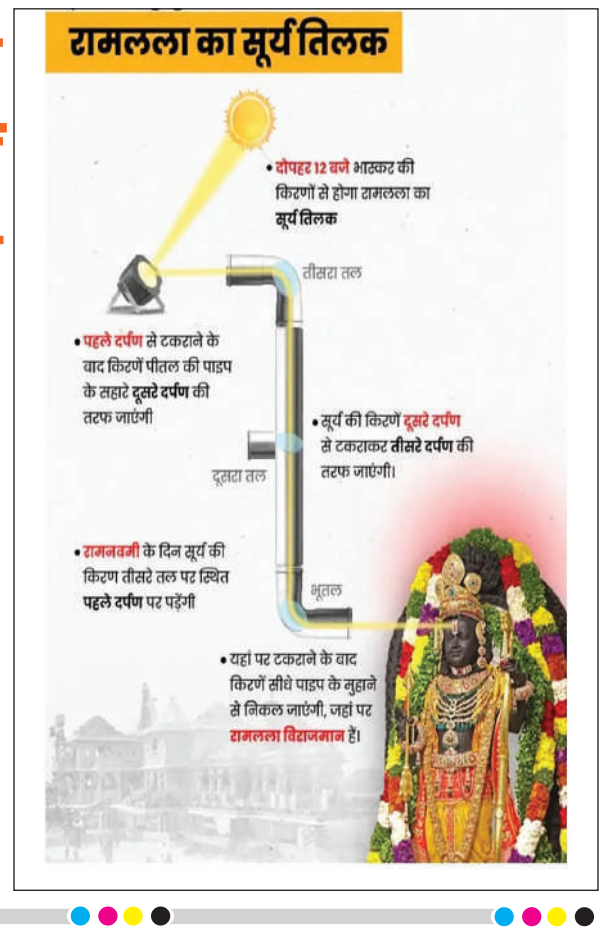

कार चालक ने बाइक सवार युवती को मारी टक्कर, फिर उसे 100 मीटर तक घसीटा; वीडियो आया सामने

परिवहन विशेष न्यूज

नंद नगरी में मोटरसाइकिल सवार युवती को कार ने टक्कर मारी। युवती के गिरने पर चालक ने उस पर कार चढ़ा दी। फिर करीब 100 मीटर तक उसे घसीटा। युवती जीटीबी अस्पताल में भर्ती है उसकी हालत गंभीर है। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है और आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मोटरसाइकिल सवार युवती को कार ने टक्कर मार दी। इसके बाद युवती के गिरने पर चालक ने उस पर कार चढ़ा दी। फिर करीब 100 मीटर तक उसे कार से घसीटा। इस घटना की सीसीटीवी वीडियो सामने आया है।

ताजा जानकारी के मुताबिक, घटना 9 अप्रैल को हुई है। वर्तमान में युवती जीटीबी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है और आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

जीटीबी की आइसीयू में भर्ती है युवती

घायल युवती का नाम अदीबा है, वह सुंदर नगर की रहने वाली है। इस समय जीटीबी में आइसीयू में भर्ती है। होश नहीं आया है। अदीबा गाजियाबाद जिले के शालीमार गार्डन के पास छाबड़ा कॉलोनी में आरओ सर्विस की दुकान पर रिसेप्शनिस्ट का काम करती है।

वहीं, मामले में स्विफ्ट कार की पहचान की गई और आरोपी सन्नी रावल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह अपने पिता के साथ एक जनरल स्टोर चलाता है।

उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी ने घटना को लेकर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर बताया कि इस संबंध में थाना नंद नगरी में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और कथित कार भी जब्त कर ली गई है। मामले में आगे की जांच जारी है।

शिक्षकों की स्थाई नियुक्ति के बाद कॉलेजों ने नहीं कराई जाति प्रमाणपत्रों की जाँच

स्थायी नियुक्तियों के बाद नियमानुसार कॉलेजों को करानी होती है जाति प्रमाणपत्रों की जाँच। विश्वविद्यालय / कॉलेज अपने स्तर पर जाति प्रमाणपत्रों की जाँच करा कर विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचित करते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। एससी/एसटी ओबीसी टीचर्स फोरम दिल्ली विश्वविद्यालय (शिक्षक संगठन) के अध्यक्ष प्रोफेसर के.पी. सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि पिछले दो वर्षों में विभागों / कॉलेजों में एससी/एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस व विकलांग के आरक्षित पदों पर हुई शिक्षकों की स्थायी नियुक्तियों के जाति प्रमाणपत्रों की जाँच कराई जाए। उन्होंने बताया है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति पिछले दो वर्षों में एससी/एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस व विकलांग के आरक्षित पदों पर हुई है, वहाँ संबंधित कॉलेजों ने अभी तक उनके आरक्षण प्रमाणपत्रों की फोरेंसिक लैब में जाँच नहीं कराई है। उनका कहना है कि सेमेस्टर परीक्षाएँ शुरू होने से पहले या आगामी शैक्षिक सत्र—2024-25 के आरंभ होने से पूर्व जाति प्रमाणपत्रों की जाँच की मांग पुनः की जा रही है। उनका कहना है कि इस समय आरक्षित पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त हुए शिक्षकों का प्रोबेशन टाइम भी पूरा हो चुका है, लेकिन कॉलेजों ने अभी तक उनके जाति प्रमाणपत्रों की जाँच नहीं कराई है।

प्रोफेसर सिंह ने बताया है कि जाति प्रमाणपत्रों की जाँच की मांग इसलिए कि जा रही है कि पिछले कई वर्षों से फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर फर्जी छात्र एडमिशन ले लेते थे जिससे आरक्षित वर्ग के हकदार छात्र समय पर प्रवेश लेने से वंचित रह जाते थे। प्रोफेसर सिंह का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार बहुत अधिक संख्या में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति हुई है। ऐसे में आनन फानन में बनाए गए जाति प्रमाणपत्रों की जाँच जरूरी हो जाती है। जाँच प्रक्रिया को व्यवस्थित करना विश्वविद्यालय / कॉलेजों की नैतिक जिम्मेदारी होती है। आरक्षित पदों पर हुई स्थायी नियुक्ति के शिक्षकों के जाति प्रमाण पत्रों की जाँच इसलिए भी जरूरी है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर संबंधी प्रावधान को जाति प्रमाणपत्र में पूरा करना आवश्यक होता है। इसी तरह कई राज्यों में एससी/एसटी, ओबीसी की जातियों में काफ़ी फेरबदल है। कुछ जातियाँ एक राज्य में एससी कटेगरी में हैं तो दूसरे राज्य में ओबीसी कटेगरी में हैं। इस तरह के जाति प्रमाणपत्रों की राज्यों के अनुसार जाँच बहुत जरूरी हो जाती है। सामान्य वर्ग की जातियों के साथ यही स्थिति उत्तर पूर्व के राज्यों में देखने को मिलती है। अतः ऐसे प्रमाणपत्रों की वैधता के लिए प्रशासनिक स्तर पर जाँच तो की ही जानी चाहिए साथ ही इसकी फोरेंसिक लैब में भी जाँच कराई जानी चाहिए।

प्रोफेसर सिंह का कहना है कि कॉलेजों में एससी/एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस व विकलांग कोटे के जाति प्रमाणपत्रों की मुकम्मल जाँच नहीं की जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज ने अपने स्तर पर कोई भी ऐसी कमेटी गठित नहीं की है जो शिक्षकों/कर्मचारियों और छात्रों के जाति प्रमाणपत्रों की जाँच करे। प्रोफेसर सिंह ने बताया है कि यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों / कॉलेजों /संस्थानों को सख्त निर्देश दिया है कि वे अपने यहाँ आरक्षित वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए और जाति प्रमाणपत्रों की जाँच के लिए एससी/एसटी, ओबीसी सेल बनाएँ। जबकि अधिकांश कॉलेजों ने इस निर्देश पर कोई ध्यान नहीं दिया है। यूजीसी का इस तरह की सेल बनाने के लिए निर्देश देने का कारण स्पष्ट था कि आरक्षित जातियों के शिक्षकों, कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति संबंधी भेद-भाव की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सके।

प्रोफेसर सिंह ने डीयू के कुलपति से यह भी मांग की है कि वह कॉलेजों के प्रिंसिपलों को एक सर्कुलर जारी करें जिसमें यह निर्देश दिया गया हो कि वह अपने कॉलेज में फॉरेंसिक लेब की व्यवस्था करें। इससे कि जाति प्रमाणपत्रों की जाँच संबंधी प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके।

प्रोफेसर के.पी.सिंह
अध्यक्ष—एससी/एसटी, ओबीसी टीचर्स फोरम, दिल्ली विश्वविद्यालय
फोन - 9868606210

दक्षिणी दिल्ली में दवाईयों के गोदाम में लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर

दक्षिणी दिल्ली के देवली गांव के पास दवाईयों के गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गयी। आग लगते वहां हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर फायर बिग्रेड की करीब आठ गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। दमकलकर्मियों द्वारा आग बुझाने का काम किया जा रहा है। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका है। आग से अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के देवली गांव के पास दवाईयों के गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गयी। आग लगते वहां हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर फायर बिग्रेड की करीब आठ गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। दमकलकर्मियों द्वारा आग बुझाने का काम किया जा रहा है। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका है। वहीं, आग से अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए और उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका में केजरीवाल ने क्या-क्या कहा?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. हालांकि, **सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया.** इसे केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में केजरीवाल ने तर्क दिया कि अगर उन्हें आगामी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया जाता है तो इससे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित होगी. ऐसा कहकर उन्होंने याचिका पर तत्कालीन सुनवाई की मांग की थी.उन्होंने कहा कि ये याचिका आपातकालीन परिस्थिति में दायर की जा रही है, क्योंकि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनावों के बीच ईडी ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया है.याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सह-आरोपियों की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर की गई है, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए हैं. ये तर्क दिया गया है कि ऐसे बयान और सबूत पिछले 9 महीनों से ईडी के पास थे और फिर भी लोकसभा चुनाव के बीच में अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई है.

ईडी की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी ने खुद का इस्तेमाल होने दिया, जिससे न सिर्फ चुनाव के बीच राजनीतिक विरोधियों की स्वतंत्रता पर हमला किया जा गया, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई.याचिका में कहा गया कि अगर केजरीवाल को आगामी चुनावी में भाग लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया गया तो ये सत्ताधारी पार्टी की ओर से चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी के प्रमुखों की गिरफ्तारी की मिसाल होगी, जिससे हमारे संविधान के मूल सिद्धांत खत्म हो जाएंगे.

हाईकोर्ट के फैसले पर क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि गवाहों के बयानों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. इसे लेकर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हाईकोर्ट इस बात को समझने में विफल रहा है कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयानों को 'पूर्ण सत्य' नहीं माना जाता है और अदालतें उन पर संदेह कर सकती हैं. इन बयानों को कभी भी तथ्यों की सच्चाई के ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे विरोधाभास और गवाह की पुष्टि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

गवाहों के बयान पर क्या कहा?

केजरीवाल की याचिका के मुताबिक, हाईकोर्ट इस बात को समझने में भी विफल रहा है कि सरकारी गवाह बन चुके सह-आरोपियों के बयान को किसी व्यक्ति के अपराध को सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टिंग प्वॉइंट नहीं माना जा सकता है. ईडी इस तरह के बयान जबरन दर्ज करवा रही है.याचिका में दावा किया गया है कि हाईकोर्ट इस बात को भी नहीं समझ पाया कि ईडी ने ऐसे बयान जमानत और दोषमुक्ति का लालच देकर दर्ज किए हैं, इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है.सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में तर्क दिया गया है कि जिन बयानों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है, उन्हें 7 दिसंबर 2022 से 27 जुलाई 2023 के बीच दर्ज किया गया था और बाद में केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है.उन्होंने दावा किया है कि पुराने बयानों को पुष्ट करने के लिए 21 मार्च 2024 को गिरफ्तारी से पहले तक कोई बयान दर्ज नहीं किया गया, जबकि प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्डिंग एक्ट की धारा 19 के तहत ऐसा करना जरूरी है. 21 मार्च 2024 यानी आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से बाहरी विचारों से प्रेरित है.

गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सी. अरविंद, मगुंटा रेड्डी और सरथ रेड्डी के बयानों पर भरोसा किया गया है, लेकिन इन बयानों से दूर-दूर तक ये संकेत नहीं मिलता है कि केजरीवाल ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत कोई कमीशन का काम किया है. दावा किया गया है कि इन बयानों से केजरीवाल के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता.उन्होंने ये भी दावा किया कि बुची बाबू और राघव मगुंटा के बयान पूरी तरह से झूठ हैं, क्योंकि वो केजरीवाल के साथ किसी भी बैठक में मौजूद नहीं थे. इसके अलावा राघव मगुंटा का बयान उन घटनाओं को शामिल करने की कोशिश करता है, जिनके बारे में उनके पिता मगुंटा रेड्डी ने कोई बात नहीं की है.इस याचिका में केजरीवाल की रिहाई और पीएमएलए की धारा 19 के तहत उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की गई है।

दिल्ली शराब नीति केस: BRS नेता के. कविता की मुसीबत बढ़ी, अब CBI ने ईडी की हिरासत से किया गिरफ्तार

सीबीआई ने बृहस्पतिवार बीआरएस नेता के. कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत से गिरफ्तार किया है। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। शनिवार को सीबीआई ने उनसे जेल के अंदर पूछताछ की थी। ईडी ने के. कविता पर आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य आप नेताओं के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया है।

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता की मुश्किलें थमती नहीं नजर आ रही हैं।

ताजा मामले में सीबीआई ने बृहस्पतिवार बीआरएस नेता के. कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत से गिरफ्तार किया है। वह फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी स्थित तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

पिछले शनिवार को सीबीआई ने उनसे जेल के अंदर पूछताछ की थी। जिसके बाद आज सीबीआई ने यह एक्शन लिया है। के. कविता आज तिहाड़ जेल में ही रहेंगी। सीबीआई ने कल शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी।

इससे पहले सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दायर कर के. कविता को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी थी। इस पर शाम को एजेंसी को आदेश मिल गया था।

23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं के. कविता

उल्लेखनीय है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल दिन मंगलवार को

के. कविता की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। इससे पहले शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ करने की अनुमति दे दी थी।

ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से लिया था हिरासत में

मालूम हो कि ईडी ने मामले में उन्हें 15 मार्च को हैदराबाद से हिरासत में लिया और अगले दिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था और 23 मार्च को अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को उनकी तीन और दिनों की हिरासत दी थी।

के. कविता पर ईडी का आरोप है कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ साजिश रची।

अरविंद केजरीवाल को एक और झटका, विजिलेंस विभाग ने दिल्ली CM के निजी सचिव को किया टर्मिनेट

शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को एक और झटका लगा है। ताजा मामले में विजिलेंस विभाग ने दिल्ली सीएम के निजी सहायक विभव कुमार को उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया है। विभव कुमार के खिलाफ 2007 के एक मामले में यह कार्रवाई की गई है।

नई दिल्ली। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में विजिलेंस विभाग की टीम ने उनके निजी सहायक विभव कुमार के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है।

जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार को उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। विजिलेंस विभाग ने विभव कुमार के खिलाफ 2007 के एक मामले में यह कार्रवाई की है, जिसमें उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और शिकायतकर्ता को गाली देने या धमकी देने का आरोप लगाया गया था।

2007 में दर्ज हुई थी FIR

विजिलेंस विभाग ने बर्खास्तगी के पीछे विभव कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को कारण बताया है। यह मामला 2007 में नोएडा प्राधिकरण में तैनात महेश पाल नामक व्यक्ति ने दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि विभव कुमार ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता, एक लोक सेवक को ₹उसके कर्तव्य का पालन करने से रोका और उसे धमकी दी।

विभव कुमार से ईडी ने की थी पूछताछ

उल्लेखनीय है कि आबकारी नीति घोटाला मामले में आठ अप्रैल दिन सोमवार को ईडी ने मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार औरआम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को भी तुगलक रोड स्थित मुख्यालय में बुलाकर दोनों से करीब छह घंटे तक पूछताछ की थी। दोनों से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दोनों को आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुछ दिन पहले ईडी ने जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा था, जिससे सोमवार को दोनों अपने-अपने तय समय पर ईडी मुख्यालय पहुंच गए थे।

शाम छह बजे विभव को छोड़ दिया गया उसके बाद दुर्गेश पाठक को भी छोड़ दिया गया। बेहद संवेदनशील मामला होने के कारण पूछताछ संबंधी जानकारी जांच एजेंसी अभी किसी से साझा नहीं कर रही है। क्योंकि इस मामले में जांच एजेंसी आगे कई नेताओं को भी गिरफ्तार कर सकती है।

21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी

ईडी ने आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उन्हें 10 दिन की कस्टडी रिमांड लेकर गहन पूछताछ की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

पैरोल जंप कर 3 साल से फरार चल रहा बदमाश गिरफ्तार, मुंबई में पहचान बदलकर रह रहा था आरोपी

पैरोल जम्पर बदमाश का पता लगाने के लिए अपराध शाखा की टीम ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए मतदाता कार्ड बनाने के लिए मुंबई में चुनाव अधिकारी के रूप में काम किया और उसकी पहचान कर मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपित अपनी दाढ़ी-मूंछ कटवाकर पहचान बदल कर रह रहा था। उसकी पहचान होने पर मुंबई से गिरफ्तार किया गया है।

नईदिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जामिया नगर के हत्या के एक मामले में पैरोल जम्प कर पिछले तीन साल से फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार किया है।

पैरोल जम्पर बदमाश का पता लगाने के लिए अपराध शाखा की टीम ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए मतदाता कार्ड बनाने के लिए मुंबई में चुनाव अधिकारी के रूप में काम किया और उसकी पहचान कर मुंबई से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान मोहम्मद मुस्ताक के रूप में हुई है। अपराध शाखा के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि 2021 में आरोपित मुस्तका और उसके दो दोस्तों का एक चाय की दुकान पर झगडा हो गया था, शिकायतकर्ता के बेटे ने इसकी जानकारी दुकान मालिक को दे दी थी।

पांचवी मंजिल से फेंक दिया था मासूम

जिस पर आरोपितों ने नाराज होकर शिकायतकर्ता को धमकी दी थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दुश्मनी के कारण तीनों आरोपितों ने अगले दिन शिकायतकर्ता के बेटे के पांचवी मंजिल से फेंक दिया।

जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपित मोहम्मद मुस्ताक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 15 मई 2021 को कोरोना महामारी के दौरान उसे 90 दिनों की आपातकालीन पैरोल पर रहा कर दिया गया था। 90 दिन बाद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और तब से फरार था।

मतदान कार्ड बनाने के लिए 500 से ज्यादा घरों में गई टीम

छह अप्रैल को आरोपित के ठिकाने के संबंध में गुप्त सूचना मिली की वह फिलहाल मुंबई में है। टीम का गठन कर तकनीकी विश्लेषण और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से, टीम ने मुंबइर् की घनी आबादी वाले गोवंडी का पता लगाया।

कोई विशिष्ठ पता नहीं था, इसलिए टीम ने चुनाव अधिकारी के रूप में काम किया और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कार्ड बनाने के लिए 500 से ज्यादा घरों में गई। अंत में आरोपित तक पहुंच उसे गिरफ्तार करने में सफल रही।

आरोपित अपनी दाढ़ी-मूंछ कटवाकर पहचान बदल रह रहा था। पूछताछ में मुस्ताक ने बताया कि पैरोल पर रिहा होने के बाद गांव गया और शादी कर ली। वहां कोई आय का साधान नहीं था और पुलिस भी उसे तलाश रही थी। इसलिए वह मुंबई चला गया और वहां कढाई गोदाम में काम करने लगा।

दिल्ली में भी खतरनाक तरीके से चलती हैं स्कूल बसें, नियमों की अनदेखी पर कटते हैं चालान; फिर भी नहीं चेत रहे ड्राइवर

हरियाणा में स्कूल बस हादसे ने देशभर के अभिभावकों का ध्यान इस ओर खींचा है। दिल्ली में जगह-जगह कैमरे और पुलिस की तैनाती के बावजूद स्कूल कैब और स्कूल बसों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है। 2022 और 2023 में स्कूल बस हादसे की घटना हो चुकी है। वहीं गलत तरीके से वाहन चलाने को लेकर भी स्कूल बस ड्राइवर पर चालान हुए हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। हरियाणा में स्कूल बस हादसे ने देशभर के अभिभावकों चिंता की बढ़ा दी है। राष्ट्रीय राजधानी में जगह-जगह कैमरे और पुलिस की तैनाती के बावजूद स्कूल कैब और स्कूल बसों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है। वर्ष 2022 की यातायात पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 141 चालान तो स्कूल बस के चालक के खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में हुए हैं। इसके अलावा गलत दिशा में स्कूल कैब व बस चलाने, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बस चलाने के मामले सामने आए। परमिट की शर्तों के उल्लंघन के भी मामले मिले हैं।

स्कूल बसों पर बढ़ानी होगी सख्ती

यातायात पुलिस की कार्रवाई के बावजूद सड़कों पर गलत तरीके से चलती हुई स्कूल बसें दिख जाती हैं, हालांकि एक राहत की बात है कि कोई भी चालान ऐसा नहीं हुआ, जिसमें बस ही अपनी उम्र पूरी कर चुकी हो। दिल्ली में स्कूल बसों व कैब की घटनाएं होती रहती है।

जनवरी व अक्टूबर 2023 में दिल्ली कैंट इलाके में स्कूल बस ने एक स्कूल वैन में टक्कर मार दी थी, जिससे कई बच्चे घायल हो गए थे। इसी तरह 12 जुलाई, 2022 को भी जीटबी एन्क्लेव इलाके में स्कूल वैन पलट गई थी, जिसमें चार बच्चे घायल हो गए थे। यह घटनाएं बताती है कि दिल्ली में यातायात नियमों के पालन कराने में खासतौर पर स्कूल बसें और वैन के लिए सख्ती बढ़ानी होगी।

141 चालान गलत तरीके से वाहन चलाने पर

वर्ष 2022 में यातायात पुलिस ने 14 स्कूल कैब चालकों का चालान सीट बेल्ट न लगाने को लेकर काटा, जबकि 12 कैब के चालान खतरनाक तरीके से वाहन चलाने को लेकर हुआ। स्कूल बस की 52 चालान वाहन चालक द्वारा सीट बेल्ट न लगाने को लेकर हुए 141 चालान खतरनाक तरीके से वाहन चालने को लेकर हुए।

स्कूल बसों के अकेले 20 चालान 2022 में यातायात सिग्नल जंप करने पर हुए। 115 चालान परमिट की शर्तों का पालन न करने पर हुए। यातायात पुलिस के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न यातायात नियमों को लेकर 505 चालान स्कूल वैन और 504 चालान स्कूल बसों के हुए।

किस-किस श्रेणी में कितने चालान

श्रेणी	वैन	स्कूल बस
यातायात सिग्नल जंप करने	3	20
बिना लाइसेंस	4	7
खतरनाक तरीके से चलाना	12	141
परमिट की शर्तों का उल्लंघन	66	115
बिना पंजीकरण	85	4

दिल्ली में स्कूल बस हादसा

17 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली कैंट इलाके में एक प्राइवेट स्कूल की तेज रफ्तार बस ने बच्चों से भरी सेंट्रल स्कूल के वैन में जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में कई बच्चे घायल हो गए।

12 जुलाई, 2022 को पूर्वी दिल्ली के जीटीबी एन्क्लेव थाना इलाके में एक प्राइवेट स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में चार बच्चे घायल हुए थे। वैन चालक फिलहाल जमानत पर है। कड़कड़डूमा कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।

पार्टी या प्रत्याशी के समर्थक ध्यान दें! जो करेगा शैतानी, उसे खानी होगी जेल की हवा

परिवहन विशेष न्यूज

लोकसभा सामान्य चुनाव संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने गाजियाबाद में चार वरिष्ठ आइएएस अधिकारी सौरभ नायक टी.अरिवाझगन अरूण कुमार सिन्हा अनिल कुमार को पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया है। चारों पर्यवेक्षक ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। चुनाव में किसी भी प्रत्याशी की मनमानी नहीं चलेगी। जो समर्थक शैतानी करेंगे उन्हें जेल की हवा खानी होगी।

गाजियाबाद। लोकसभा चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए गाजियाबाद में चार पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। चारों वरिष्ठ आइएएस अधिकारी हैं। चुनाव की बैठक में उन्होंने रूख स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी कामकाज व प्रक्रिया में जरा भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चुनाव में किसी भी प्रत्याशी की मनमानी नहीं चलेगी। जो समर्थक शैतानी करेंगे, उन्हें जेल की हवा खानी होगी।

चारों पर्यवेक्षकों के तैनात होने के बाद जिले के अधिकारी भी अलर्ट मोड में आ गए हैं क्योंकि पर्यपेक्षक सभी तैयारियों की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। जरा की लापरवाही मिली तो कड़ी कार्रवाई तय है। इसके चलते जिला प्रशासन के अधिकारी तैयारियों की खुद से दोबारा समीक्षा कर रहे हैं ताकि कोई कमी न रहे।

दरअसल, लोकसभा सामान्य चुनाव संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने गाजियाबाद में चार वरिष्ठ आइएएस अधिकारी सौरभ नायक, टी.अरिवाझगन, अरूण कुमार सिन्हा, अनिल कुमार को पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया है। चारों पर्यवेक्षक ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। देखा जा रहा है कि चुनाव संबंधित शिकायतों का निस्तारण सही ढंग से गुणवत्ता पूर्ण हो रहा है या नहीं।

प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव में खर्च कर सकता है 95 लाख

जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम गाजियाबाद इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। चुनावी खर्च की निगरानी के लिए तैनात किए गए दो पर्यवेक्षक सौरभ नायक व टी.अरिवाझगन ने बताया कि सभी प्रत्याशी अपने चुनाव संबंधित व्यय को निर्वाचन में पंजीकृत बैक खाते से ही व्यय करें।

भारत निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा 95 लाख रुपये तय की है। प्रत्येक प्रत्याशी 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। सभी प्रत्याशी अपना व्यय रजिस्टर बनवा लें और सभी लेनदेन पंजीकृत खाते से ही करें। प्रत्येक प्रत्याशी केवल 10 हजार रुपये नकद खर्च कर सकता है।

दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव ओमेश सहगल कहते हैं कि नए मंत्री के नाम की सिफारिश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं।

सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण फंसा दिल्ली का सबसे बड़ा पेंच, खुद एलजी सक्सेना भी नहीं ले सकते निर्णय

परिवहन विशेष न्यूज

नए मंत्री के नाम की सिफारिश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वह हिरासत में हैं और जेल नियमावली वहां से उनको कोई सरकारी कामकाज करने की इजाजत नहीं देती तो पेच फंसने की संभावना है। यहां तक कि आनंद के विभागों को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर अन्य मंत्रियों में बांटने की संस्तुति भी सीएम के माध्यम से ही एलजी को भेजी जा सकती है।

नई दिल्ली। आप सरकार की छह सदस्यीय कैबिनेट में से एक रहे राजकुमार आनंद ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन उनके स्थान पर नए मंत्री की नियुक्ति हाल फिलहाल संभव नहीं लग रही। सीएम अरविंद केजरीवाल का जेल में होना इसमें सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। अगले कुछ दिनों में उनके बाहर आने की संभावना भी नहीं ही लग रही।

दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव ओमेश सहगल कहते हैं कि नए मंत्री के नाम की सिफारिश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वह हिरासत में हैं और जेल नियमावली वहां से उनको कोई सरकारी कामकाज करने की इजाजत नहीं देती, तो पेच फंसने की संभावना है। यहां तक कि आनंद के विभागों को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर अन्य मंत्रियों में बांटने की संस्तुति भी सीएम के माध्यम से ही एलजी को भेजी जा सकती है। एलजी स्वयं से निर्णय नहीं ले सकते।

CM की संस्तुति से ही होगा कोई बदलाव: एसके शर्मा

पूर्व लोकसभा सचिव एस के शर्मा कहते हैं कि अधिकारियों के स्तर पर अभी भी सारे कामकाज पहले की तरह होते रहेंगे। चूंकि आचार संहिता लगी हुई है तो कोई बड़ा निर्णय या घोषणा वैसे भी प्रतिबंधित है। लेकिन हां, ऐसी स्थिति में राजनिवास को किसी भी बदलाव की संस्तुति सीएम ही कर सकते हैं।

सारा विशेषाधिकार LG और केंद्र के पास: योगेंद्र नारायण

वहीं राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण ने कहा कि ऐसी स्थिति पहली बार उत्पन्न हो रही है। पूर्व में जिस भी मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा, उसने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। मौजूदा प्रकरण में भी अदालत ने कोई हस्तक्षेप करने से पहले ही इनकार कर चुकी है और जेल नियमावली में भी इस तरह के मामलों में न हां स्पष्ट है, न ही ना। यहां सारा विशेषाधिकार एलजी और केंद्र सरकार का है। जेल भी उन्हीं के अधीन है। अगर वह चाहेंगे तो सीएम को अनुमति दी भी जा सकती है और नहीं चाहेंगे तो फिर नहीं ही मिल पाएगी।

रीजन की 150 से 200 बसें लगेंगी चुनाव में, यात्रियों को झेलनी पड़ेगी परेशानी

अब तक परिवहन निगम करीब 27 बसें दे चुका है। प्रत्येक चरण में करीब 150 से 200 बसें चुनाव में आरक्षित रहेंगी। इससे रोजाना हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। बसों के चुनाव में लगने से कई शहरों का संचालन प्रभावित हो जाएगा। जिस मार्ग पर हर 30 मिनट या एक घंटे में बस चलती है। उसका संचालन का समय दोगुना कर दिया जाएगा।

साहिबाबाद। लोकसभा चुनाव सात चरणों में होने हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। इसके लिए पुलिस आयुक्त ने पुलिस बल को मतदान केंद्रों तक भेजने के लिए परिवहन निगम से बसों की मांग की है। अब तक परिवहन निगम करीब 27 बसें दे चुका है। प्रत्येक चरण में करीब 150 से 200 बसें चुनाव में आरक्षित रहेंगी। इससे रोजाना हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी।

गाजियाबाद रीजन के सभी आठ डिपो कौशांबी, साहिबाबाद, लोनी, गाजियाबाद, खुर्जा, बुलंदशहर, हापुड़ व सिकंद्राबाद में परिवहन निगम की 722 रोडवेज बसें हैं। इसके अलावा 209 बसें अनुबंधित हैं। चुनाव में केवल निगम की बसों को लगाया जा रहा है। इसके लिए रीजन के प्रत्येक डिपो से बसों को लिया जाएगा।

संचालन का समय कर दिया जाएगा दोगुना

बसों के चुनाव में लगने से कई शहरों का संचालन प्रभावित हो जाएगा। जिस मार्ग पर हर 30 मिनट या एक घंटे में बस चलती है। उसका संचालन का समय दोगुना कर दिया जाएगा। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। जिस मार्ग पर जितनी बसें कम होंगी उतना ही अधिक समय इंतजार करना पड़ेगा।

अभी गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, एटा, गौंडा समेत ज्यादातर लंबे मार्गों पर हर एक से दो घंटे पर बस का संचालन किया जा रहा है। चुनाव में बसें आरक्षित होने से दो से चार घंटे हो जाएगा। भीषण गर्मी में यात्रियों के पसीने छूट जाएंगे।

हर बार चुनावों में झेलनी पड़ती है परेशानी

हर बार विधानसभा व लोकसभा चुनावों के लिए परिवहन निगम की रोडवेज बसों को आरक्षित कर लिया जाता है। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। ये परेशानी सभी चरणों में चुनाव होने तक ही जारी रहती है। क्योंकि बसों को किसी भी शहर में भेज दिया जाता है।

दूसरे चरण में तीन हजार पुलिस बल के लिए बसों की डिमांड

शहर	बसें
बिजनौर	36
अमेठी	01
मुजफ्फनगर	19
फतेहगढ़	01
उन्नाव	01
कौशांबी	01
मुरादाबाद	10

चुनाव के लिए रोडवेज बसों की मांग की गई है। करीब 27 बसें उपलब्ध करा दी गई हैं। करीब 150 से 200 बसों को चुनाव में भेजना पड़ेगा। बसों की संख्या कम होने पर संचालन का टाइम बढ़ा दिया जाएगा। यात्रियों को परेशानी न हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा।

-केसरी नंदन चौधरी, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

लोकसभा चुनाव में एक नये अध्याय की शुरुआत हो

ललित गर्ग

एक सफल, सार्थक, समर्थ एवं चरित्रसम्पन्न विपक्षी नेतृत्व की आवश्यकता हर दौर में रही है, लेकिन आज यह ज्यादा तीव्रता से महसूस की जा रही है। विपक्षी नेतृत्व कैसा हो, उसका अपना साथियों के साथ-साथ सत्तापक्ष के साथ कैसा सलूक हो?

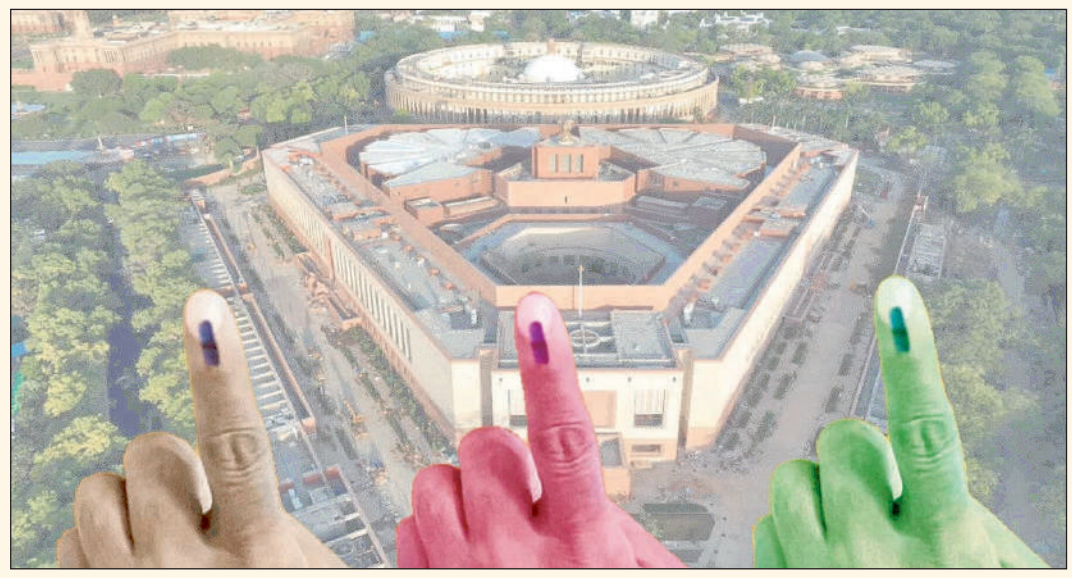

लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान सज गया है, सभी राजनीतिक दलों में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला हमेशा की तरह परवान चढ़ने लगा है। राजनीति में स्वच्छता, नैतिकता एवं मूल्यों की स्थापना के तमाम दावों के अनैतिकता, दल-बदल, आरोप-प्रत्यारोप की हिंसक मानसिकता पसरी है। राजनेता दलबदल की ताल ठोक रहे हैं। दलबदलुओं को टिकट देने में कोई दल पीछे नहीं रहा, क्योंकि सवाल, येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतने तक जो सीमित रह गया है। सिद्धांतों और राजनीतिक मूल्यों की परवाह कम ही लोगों को रह गई है। चुनावी राजनीति देश के माहौल में कड़वाहट घोलने का काम भी कर रही है। स्वस्थ एवं मूल्यपरक राजनीति को किनारे किया जा रहा है। राजनीति पूरी तरह से जातिवाद, बाहुबल और धनबल तक सिमट गई है। हालत यह है कि अब तक राजनीति दलों ने जिन प्रत्याशियों को उतारा है, उनमें आधे से अधिक दलबदलू, अपराधी अथवा दागी हैं। ऐसे में राजनीति के स्तर में सुधार की उम्मीद आखिर कौन, किससे करे? इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की चुप्पी तो समझ में आती है, लेकिन चुनाव आयोग की खामोशी समझ से परे है।

लोकसभा चुनाव नेतृत्व चयन का ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण अवसर है, इस अवसर पर लाओत्जु ताओ ते चिंग की पुस्तक ''द ताओ ऑफ लीडरशिप'' राजनीति एवं राजनेताओं के लिये एक रोशनी है। यह एक अद्भुत, अद्वितीय एवं अप्रतिम कृति हैं जो नये युग के लिए नेतृत्व की रचनात्मक व्यूह रचना प्रस्तुत करती है। आज जबकि देश और दुनिया में सर्वत्र नेतृत्व के प्रश्न पर एक घना अंधेरा छाया हुआ है, निराशा और दायित्वहीनता की चरम पराकाष्ठा ने राजनीति एवं नेतृत्व को जटिल दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। समाज और राष्ट्र के समुचे परिदृश्य पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमें जिन विषम और जटिल परिस्थितियों से रू-ब-रू होना पड़ता है, उन विषम हालातों के बीच ठीक से राह दिखाने वाला कोई नेतृत्व नजर नहीं आता।

यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र धुंधलका सब देख रहे हैं, लेकिन खामोशी के साथ। शायद सबकी अपनी-अपनी मजबूरियां हैं। मतदाता की मजबूरी यह है कि आखिर उसे मैदान में डटे उम्मीदवारों में से ही एक को चुनना है। इस देश ने महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, गरीबी, साम्प्रदायिकता के खिलाफ भी जनता को सड़कों पर उतरते देखा है लेकिन राजनीति में टकराव, अपराध, देश-विरोध और हिंसा की राजनीति के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ। चुनाव आयोग की अपनी सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन जेल में बैठे-बैठे लोग चुनाव लड़ भी लेते हैं और जीत भी जाते हैं। खलनायक नायक बनने लगे हैं। चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम खर्च की सीमा सरेआम ध्वस्त होती है, लेकिन आयोग कुछ कर नहीं पाता। चुनाव प्रचार के दौरान अपशब्दों का उच्चारण-गालीगलोच खुल्लम-खुल्ला होता है, लेकिन आयोग नोटिस देकर ही अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। मतदाताओं के वोट खरीदने के लिए उन्हें सरेआम पैसे ही नहीं शराब तक बांटी जाती है, लेकिन किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जनता राजनीति के गिरते स्तर से त्रस्त तो है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती। इन लोकसभा चुनाव में यह चुप्पी टूटनी चाहिए और आजादी के अमृतकाल को अमृममय बनाने वाला नेतृत्व सामने आना चाहिए। ऐसा नेतृत्व जो देश को अग्रणी आर्थिक महाशक्ति के रूप में ले जाये एवं विकास की स्वर्णिम गाथा को गढ़े।

एक सफल, सार्थक, समर्थ एवं चरित्र सम्पन्न विपक्षी नेतृत्व की आवश्यकता हर दौर में रही है, लेकिन आज यह ज्यादा तीव्रता से महसूस की जा रही है। विपक्षी नेतृत्व कैसा हो, उसका अपना साथियों के साथ-साथ सत्तापक्ष के साथ कैसा सलूक हो? उसमें क्या हो, क्या न हो? वह क्या करे, क्यों करे, कब करे, कैसे करे? इत्यादि कुछ जटिल एवं गंभीर प्रश्न हैं जिनके जवाब ढूंढ़े बिना हम एक सक्षम विपक्षी नेतृत्व को उजागर नहीं कर सकते। इन प्रश्नों के उत्तरों की कसौटी पर ही हमें आने वाले सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के नेतृत्व को कसना होगा। जिस नेतृत्व के पास इन प्रश्नों के उत्तर होंगे, जो समयज्ञ होगा, सहिष्णु होगा, तटस्थ होगा, दूरदर्शी होगा, निःस्वार्थी होगा, वैसा ही नेतृत्व जिस राष्ट्र को प्राप्त होगा, उसकी प्रगति को संसार की कोई शक्ति बाधित नहीं कर सकेगी। ऐसा ही नेतृत्व नया इतिहास बना सकेगा और भावी पीढ़ी को उन्नत दिशाओं की ओर अग्रसर कर सकेगा। आज चुनाव प्रचार में जिस तरह की आरोप-प्रत्यारोप की हिंसक संस्कृति पनपी है, एक दूसरे पर जूते-चप्पल फेंके जाते है, पत्थर से हमला किया जाता है, छोटी-छोटी बातों पर अभद्र शब्दों का व्यवहार, हो-हल्ला, छींटाकशी और हंगामा आदि घटनाएं ऐसी है जो नेतृत्व को धुंधलाती है।

नेतृत्व को लेकर लोगों की मानसिकता में बहुत बदलाव आया है, आज योग्य नेतृत्व की प्यासी परिस्थितियां तो हैं, लेकिन बदकिस्मती से अपेक्षित नेतृत्व नहीं हैं। जलाशय है, जल नहीं है। नगर है, नागरिक नहीं है। भूख है, रोटी नहीं है-ऐसे में हमें सोचना होगा कि क्या नेतृत्व की इस अप्रत्याशित रिक्तता को भरा जा सकता है? क्या राष्ट्र के सामने आज जो भयावह एवं विकट संकट और दुविधा है उससे छुटकारा मिल सकता है? हालही में नेतृत्व के प्रश्न पर एक करारा व्यंग्य पढ़ा था- 'देश और ट्रेन में यही अंतर है कि ट्रेन को लापरवाही से नहीं चलाया जा सकता।' यानी देश के संचालन में की गई लापरवाही तो क्षम्य हैं पर ट्रेन के पटरी से उतरने में की गई लापरवाही क्षम्य नहीं, क्योंकि इसके साथ आदमी की जिंदगी का सवाल जुड़ा है। मगर हम यह न भूलें कि देश का नेतृत्व अपने सिद्धांतों और आदर्शों की पटरी से जिस दिन उतर गया तो पूरी इन्सानियत एवं राष्ट्रीयता की बरबादी का सवाल उठ खड़ा होगा।

आज देश में लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक, नैतिक जीवन-मूल्यों के मानक बदल गये हैं न्याय, कानून और व्यवस्था के उद्देश्य अब नई व्याख्या देने लगे हैं। चरित्र हासिए पर आ गया, सत्ता केन्द्र में आ खड़ी हुई। ऐसे समय में कुर्सी पाने की दौड़ में लोग जिम्मेदारियां नहीं बांटते, चरित्र बांटने लगते हैं और जिस देश का चरित्र बिकाऊ हो जाता है उसकी आत्मा को फिर कैसे जिन्दा रखा जाए, चिन्तनीय प्रश्न उठा खड़ा हुआ है। आज कौन अपने दायित्व के प्रति जिम्मेदार है? कौन नीतियों के प्रति ईमानदार है? इस संदर्भ में आचार्य तुलसी का कथन यथार्थ का उद्घाटन करता है कि ''ऐसा लगता है कि राजनीतिज्ञ का अर्थ देश में सुव्यवस्था बनाए रखना नहीं, अपनी सत्ता और कुर्सी बनाए रखना है। राजनीतिज्ञ का अर्थ उस नीतिनिपुण व्यक्तित्व से नहीं, जो हर कीमत पर राष्ट्र की प्रगति, विकास-विस्तार और समृद्धि को सर्वोपरि महत्व दें, किन्तु उस विदूषक-विशारद व्यक्तित्व से है, जो राष्ट्र के विकास और समृद्धि को अवनति के गर्त में फेंककर भी अपनी कुर्सी को सर्वोपरि महत्व देता है।'' राजनैतिक लोगों से महात्मा बनने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, पर वे पशुता पर उतर आएं, यह ठीक नहीं है।

वर्तमान विपक्षी नेतृत्व की सबसे बड़ी विसंगति और विषमता यह है कि वह परदोषदर्शी है, जो सत्तापक्ष की अच्छाई में भी बुराई देखने वाले हैं। यह नेतृत्व कुटिल है, मायाबी है, नेता नहीं, अभिनेता है, असली पात्र नहीं, विदूषक की भूमिका निभाने वाला है। यह नेतृत्व सत्ता- प्राप्ति के लिये कुछ भी करने से बाज नहीं आता, यहां तक जिस जनता के कंधों पर बैठकर सत्ता तक पहुंचने के लिये जैसी राजनीति यह कर रहा है, घोषणा-पत्रों में जनता को ठगने एवं लुभाने के जो प्रयास हो रहे हैं, वे एक तरह से जनता की पीठ में भी सबसे पहले छुरा भोंकते हुए प्रतीत होते हैं। इससे भी अधिक घातक है इस नेतृत्व का असंयमी, अपराधी और चरित्रहीन होना, जो सत्ता पर काबिज होने के लिये राष्ट्र से भी अधिक महत्व अपने परिवार को देता है। देश से भी अधिक महत्व अपनी जाति और सम्प्रदाय को देता है। चुनाव जीतना जिनके लिये सेवा का साधन नहीं, विलास का साधन है। नेतृत्व का चेहरा साफ-सुथरा बने, इसके लिये अपेक्षित है कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों के चरित्र का परीक्षण हो। आई-क्यू टेस्ट की तरह करेक्टर टेस्ट की कोई नई प्रविधि प्रयोग में लाई जाये तो यह लोकसभा चुनाव का संग्राम अधिक सार्थक होगा।

जब भारत देश की राजधानी में उच्च न्यायालय के आदेश और उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने बाद परिवहन विभाग के आला अधिकारी बेखौफ ऐसा करवा रहें हैं तो और कही ऐसा तो क्या ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। **वाराणसी शहर की प्रमुख चौराहा और गलियों में 20 हज़ार चल रही टोटो की वजह से भीषण जाम की समस्या,प्रशासन कर रहा अनदेखी** धार्मिक और पर्यटन नगरी काशी की यातायात व्यवस्था में 20437 पंजीकृत (टोटो) ई-रिक्शा खलल डाल रहे हैं। प्रमुख 10 चौराहे और 10 क्षेत्रों में जाम का कारण बनने वाले रोजाना 15-20 ई-रिक्शा सीज और 20-30 का चालान की कार्रवाई के बाद भी कोई डर नहीं रह गया है। करीब 800 अवैध ई-रिक्शा भी गलियों और कॉलोनियों में दौड़ रहे हैं।

अस्सी-जंगमबाड़ी मार्ग, गिरजाघर चौराहा-नई सड़क और लंका-सामनेघाट मार्ग, कैंट-इंग्लिशिया लाइन तिराहा और मैदागिन-विशेश्वरगंज, सिटी स्टेशन और नक्खीघाट मार्ग, भोजूबीर-अर्दली बाजार मार्ग और पांडेयपुर चौराहा पर सबसे अधिक यातायात व्यवस्था में बाधा ई-रिक्शा पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा रोडवेज कैंट, परेडकोठी मार्ग, भेलूपुर, कमच्छा, कबीरचौरा, जगतगंज, रामकटोरा, सुंदरपुर-खोजवा, पांडेयपुर चौराहा, पहड़िया और नाटी इमली आदि क्षेत्रों में भी ई-रिक्शा के बेतरतीब खड़े होने और संचालन से सुबह से लेकर रात तक जाम की स्थिति बनी रहती है। महीने दर महीने ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। **सब्जी, फल की दुकान और मजदूरी छोड़कर चला रहे टोटो** यातायात पुलिस के अनुसार ई-रिक्शा चलाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले जो फल, सब्जी, चाट की दुकान लगाते थे या मजदूरी करते थे, वह भी अब ई-रिक्शा चला रहे हैं। कोई खुद का तो अधिकतर किराये पर लेकर चला रहे हैं। लंका के भगवानपुर समेत अन्य क्षेत्रों में रहने वाले एक व्यक्ति पांच से छह ई-रिक्शा खरीदकर उसे 500 से 1000 रुपये प्रति दिन किराये पर चलवा रहा है। दिन और रात में ई-रिक्शा चलाकर चालक 1500 से 2000 रुपये रोजाना कमा ले रहा है। **रजिस्ट्रेशन नंबर पर बांधते हैं चुनरी, कमांड सेंटर भी नहीं पकड़ पाता** अवैध ई-रिक्शा की शहर में इंट्री रोकने के लिए यातायात पुलिस सिटी कमांड सेंटर का भी सहारा लेती है। बेतरतीब तरीके से चलने वाले ई-रिक्शा वाले या तो अपने

रजिस्ट्रेशन नंबर उतार देते हैं या फिर नंबर प्लेट पर चुनरी व रूमाल जैसा कपड़ा बांध देते हैं, जिससे उसकी पहचान भी न हो सके। गिरजाघर, नई सड़क, सोनारपुरा, कैंट रेलवे स्टेशन, सिटी स्टेशन के आसपास इनकी संख्या ज्यादा होती है। **बैटरी बचाने को रात में हेड लाइट रखते हैं बंद** कैंट स्टेशन-परेडकोठी मार्ग हो या फिर इंग्लिशिया लाइन से विद्यापीठ रोड आदि रूटों पर कम उम्र के किशोर के हाथों में ई-रिक्शा की कमान होती है। अक्सर रात में यह लाइट बंद करके निकलते हैं। ताकि बिजली की खपत और बैटरी कम खर्च हो। ऐसे में हादसे भी होते हैं। **अधिकारी बोले** ई-रिक्शा के रूट निर्धारण और तीन जोन में कलरकोड व्यवस्था को लेकर प्रारूप बन रहा है। इसे लेकर ई-रिक्शा, ऑटो यूनियन पदाधिकारियों संग बैठक भी हो गई है। क्यूआर कोड, स्टीकर मैटेरियल्स आदि मंगाए जा रहे हैं।

-राजेश कुमार पांडेय, एडीसीपी, यातायात **जनता का प्रशासन से सवाल ?** वाराणसी शहर की जाम समस्या और यातायात को लेकर वाराणसी शहर के कुछ जगहों पर लोगों से संवाद किया तो (अपना नाम न छापने की शर्त पर) कुछ प्रमुख समस्याएं सामने आई है, जो निम्न है।

1. सबसे पहले तो प्रशासन ने वाराणसी को जाम से मुक्त करने के लिए कई योजनाएं बनाई लेकिन उन्हें धरातल पर लागू करवाने में असफल रही।

2. इसके बाद टोटो नाबालिक बच्चों द्वारा संचालित किया जाना रहा, जो कि प्रशासन के सामने निर्भिक होकर धड़ल्ले से चला रहे है। और गिने चुने यातायात वह पुलिसकर्मी सिर्फ कुछ पैसे के लिए उनके नाजायज संचालन को बढ़ावा दे रहे है।

3. यात्रियों की जान खतरे में डालकर सवारी से अधिक संख्या में बैठाना और सड़कों व गालियों में तेजी से टोटो का चलाना।

4. नंबर प्लेटपर चुनरी बांधकर चालान काटे जानें का डर न होना, और धड़ल्ले से संचालन करना।

5. हमेशा ओवरटेक में लगे रहना, और एक लाइन में नही चलना।

6. ज्यादा पैसे कमाने की होड़ में अभिवाहको द्वारा अपने नाबालिक बच्चों को टोटो चलाने के लिए प्रोत्साहन देना।

7. सिटी तो सिटी हाईवे पर भी धड़ल्ले से टोटो का संचालन होना।

8. सबसे बड़ी चीज प्रशासन द्वारा रूट और किराया निर्धारित होने के बावजूद टोटो और टैंपो द्वारा उनका पालन नहीं करना।

आखिर में इन सभी सवालों का जबाव जनता को कौन देगा ? यह जाम कि समस्या कब खत्म होगी ? **प्रशासन के साथ-साथ आम जनमानस की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुहिम पर ईमानदारी से पहल करे तभी यह भीषण जाम (कैंसर) खत्म की समस्या का प्रयास सफल होगा।**

एक बार फिर दिल्ली सरकार की तेज रफ्तार बस खंभे से टकराई, 15 यात्री हुए घायल...

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के राजा गार्डन रिंग रोड पर एक क्लस्टर बस का अचानक से संतुलन काफी बिगड़ा और वो सीधे जाकर खंभे से टकरा गई. जिसकी वजह से बस में बैठे हुए 15 लोग घायल हो गए. ऐसा कहा गया है कि बस धौला कुआं से पंजाबी बाग की और जा रही थी. इस हादसे में बस काफी क्षतिग्रस्त हो गई. घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में ले जाया गया. बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी. रिंग रोड पर दाएं और फ्लाईओवर के लिए एक खाली रास्ता जा रहा है जबकि बाएं और राजौरी गार्डन के लिए. बीएस की गति तेज होने के कारन से ड्राइवर यह नहीं सोच पाया कि फ्लाईओवर पर जाना है या फिर बाएं ओर. इसी बीच बस सीधा डिवाइडर पर चल गयी और डिवाइडर पर लगे खंभे से टकराई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की. यह कोई एक बार नहीं हुआ जब डीटीसी की क्लस्टर बस का एक्सीडेंट हुआ हो. पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू है, उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। **क्या दिल्ली के परिवहन मंत्री, आयुक्त परिवहन और एमडी डीटीसी इस तरह लगातार हो रहे हादसो पर जनता को कोई जवाब देंगे, बड़ा सवाल ?**

जनता के जान माल की चिंता करना इन्ही का पहला दायित्व है पर अफसोस, इतनी बसों में चलते हुए आग लगी, कितनी बसों के चलते हुए हिस्से गिरे, कितनी बसे रोज सड़को पर खड़ी हो जाती है और कितने हादसे हो चुके पर परिवहन मंत्री, आयुक्त परिवहन, विशेष आयुक्त परिवहन और एमडी द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो।

"वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आसके देश के काम नहीं।"

सुभाष चंद्र बोस अगर आज होते तो शायद, सड़क सुरक्षा पर भी कुछ बोलते। आज सड़क पर जो हादसे हो रहे हैं, उसमें मूल रूप से सबकी जवाबदेही है।

कभी कभी लगता है, 'ॐ इग्नोराये नमः' #OmIgnoraiNamha करते चलो, सब ठीक है - क्या फर्क पड़ता है ? तभी ज़मीर से आवाज़ भी आती है, आज तुम चुप हो कल कोई और चुप रहेगा। जब बोलना था, तब बोले नहीं अब सहो। 'जैसी नियत, वैसी ही नियति बन जाती है।'

कभी फरीदाबाद के बॉर्डर पर 'हरियाणा जहां दूध दही का खांडा' लिखा होता था, आज #Daaru के इतने ठेके हैं कि हर मोड़ पर ठेकों के नाम से पहचान होने लगी है। तो आज का विषय ही यही - ये भी सही है, वो भी सही है।

'गलत कुछ नहीं होता, सब नजरिए की बात है। क्योंकि खुश रहने का एक बीज मंत्र है, आप ही सही हैं।'

सेंदरी ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एनएचएआई बनाएगा बाईपास

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्राधिकरण के अधिकारी ने दी जानकारी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राज्य की खराब सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि सेंदरी ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक बाईपास बनाया जाएगा। इसके लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके लिए जल्द ही अवार्ड पारित कर दिया जाएगा और काम शुरू होगा। ज्ञात हो कि प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर दायर हिमांक सलूजा व अन्य की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई चल रही है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दो सप्ताह बाद इस मामले में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई में न्याय मित्र राजीव श्रीवास्तव और प्रतीक शर्मा ने मुंगेली, पंडरिया और कवर्धा को जोडने वाली सडक़ों के खराब होने के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके अलावा बिलासपुर से धनेली होते हुए विधानसभा जाने वाली धनेली की सडक़ के मरम्मत की आवश्यकता बताई गई थी। दोनों मामलों में कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इनके लिए टेंडर आचार संहिता लागू होने के बावजूद जारी किए जाएं, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर आचार संहिता लागू नहीं होती।

पर्यटन और धार्मिक क्षेत्र में 27 रोप-वे शुरू करने की मंजूरी

परिवहन विशेष न्यूज

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक पर्यटन, पर्यटन क्षेत्र और यातायात को सुगम बनाने, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 27 रोप-वे बनाने का निर्णय लिया है। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने चार रोपवे बनवाने की अनुमति दी थी। अब 23 और नए पर्यटन स्थलों में रोप-वे बनाने की मंजूरी दी है।

मध्य प्रदेश सरकार ने पहले उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल तक 2 किलोमीटर का रोप-वे बनाने की अनुमति दी थी। जबलपुर में एवेन्यू मॉल सिविक सेंटर से मालवीय चौराहा और बलदेवबाग तक रोप-वे की अनुमति दी थी। जबलपुर में ही अंपायर स्टेडियम से गुरुद्वारा वाया रामपुर चौक की अनुमति दी गई थी। सागर में विक्टोरिया माता मंदिर से फनीकुलर से आईटीआई तक रोप-वे बनाने की अनुमति दी थी।

अब जो नए 23 रोप-वे तैयार किए जाएंगे। उनमें राम राजा मंदिर से लेकर ओरछा तक, नर्मदा तट से सैलानी टापू ओंकारेश्वर तक, सिद्धवरकूट जैन मंदिर से राजेश्वरम आश्रम तक, खजुराहो स्नेहफाल से केन नदी तक, रायसेन स्टेशन पार्किंग से रायसेन किला तक, दतिया में स्टेशन से बगलामुखी माता मंदिर तक, इंदौर में रीगल चौराहे से राजवाड़ा तक। पचमढ़ी में शिव मंदिर पार्किंग से चौरागढ़ शिव मंदिर तक।
पातालकोट, तामिया व अमरकंटक मे दूध धारा से कपिलधारा तक, ग्वालियर किला से

फूल बाग तक, मांडू प्रवेश द्वार से रूपमती महल तक, भोपाल में वन विहार से खानू गांव तक, कोलार रोड से न्यू मार्केट तक, कोकता ट्रांसपोर्ट नगर से नादरा बस स्टैंड वाया गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में रोपवे तैयार किए जाएंगे।

केंद्रीय पर्वतमाला स्कीम में केंद्र सरकार 60 फ़ीसदी की आर्थिक मदद करता है। बाकी का खर्च राज्य सरकार करेगी। यह रोप-वे पीपी मोड में सरकार संचालित कर सकती है। अभी इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। एक रोप-वे को तैयार करने में लगभग 2 से 3 साल का समय लगता है। रोपवे की गति 6 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से रहती है। पर्यटन को लुभाने और यातायात को सुगम मनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 27 रोपवे में शुरू किया जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में रोप-वेमध्य प्रदेश में अभी सल्कनपुर मंदिर, भोपाल के महावीर मंदिर, मैहर मैं शारदा माता, जबलपुर में भेड़ाघाट, देवास में माता टेकरी, चित्रकूट के कामदगिरी परिक्रमा पथ और लक्ष्मण पहाड़ी पर सफलता पूर्वक रोप-वे संचालित किये जा रहे हैं।

5 दिन में 10 मौत- सांसद ने बढ़ते दुर्घटनाओं पर पुलिस व प्रशासन से किया सवाल,क्या कर रहे हैं उपाय ?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। कोरबा जिले के बालको क्षेत्र में रूमगड़ा बालको मार्ग पर बुधवार देर रात भारी वाहन की टक्कर से तीन युवकों की असामयिक दर्दनाक मौत पर कोरबा लोकसभा की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने गहरा दुःख व्यक्त किया है। सांसद ने जिले में बढ़ते सड़क हादसों के मामलों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों से कड़े शब्दों में सवाल किया है कि आखिर वे कर क्या रहे हैं ? पिछले 5 दिनों के भीतर विभिन्न सड़कों पर 10 से अधिक मौतें हुई हैं जो यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला है। सांसद ने कहा है कि इसी साल मार्च महीने में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक उन्होंने ली थी और बैठक में कलेक्टर श्री अजीत वसंत, जिला पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ

तिवारी, जिला परिवहन अधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए दुर्घटनाओं का कारण जानकर उसका विश्लेषण करते हुए उचित उपाय करने की बात कही थी लेकिन जिस तरह से जिले से गुजरे हुए नेशनल हाईवे से लेकर आम सड़कों पर हादसों की संख्या बढ़ रही है, वह जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की नाकाम कोशिशों को दर्शाता है। सांसद ने कहा कि भारी वाहनों की रफ्तार पर नियंत्रण के लिए उचित उपाय किया जाना जरूरी है, जिसके लिए प्रशासन गंभीरता दिखाए। हर दिन हादसे में किसी की मौत हो रही है तो कोई अपंग हो रहा है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है लेकिन प्रशासन सिर्फ हादसों के विश्लेषण में ही लगा हुआ है। आखिर वे किस तरह का उपाय कर रहे हैं जो कारगर साबित नहीं हो रहा और रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही है। सांसद श्रीमती महंत ने कहा है कि दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक उपक्रम एसईसीएल, बाल्को, पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे, एनएचएआई, एनएचपीडब्ल्यूडी, परिवहन, यातायात विभाग के अधिकारियों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी लेकिन वे भी गंभीर नहीं हैं। आवश्यकतानुसार सड़कों पर संकेतक लगाने, मरम्मत योग्य सड़कों का शीघ्रता से मरम्मत करने, धूल उड़ने वाले मार्गों पर नियमित पानी का छिड़काव करने तथा सड़क पर जाम लगने से रोकने के लिए भारी वाहन चलने वाले मार्ग के आसपास पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही आवश्यक ब्रेकर तथा संकेतक लगाने के कार्यों में भी कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही है। शहर के भीतर दिन भर जाम में लोग उलझ रहे हैं, यातायात की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है लेकिन अभी तक सिर्फ उपाय ही हो रहे हैं, जो चिंताजनक है।

इलेक्ट्रीक वाहनों को चार्ज करते टाइम इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। मौजूदा समय में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते और बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए लोगों के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ रही है. ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने के लिए उन्हें बेहतर तरीके से चार्ज करना काफी जरूरी है. ज्यादातर लोग वाहन को चार्ज करने में कई गलतियां करते हैं. इसकी वजह से व्हीकल की बैटरी जल्दी खराब हो जाती है. ऐसे में व्हीकल में आग लगने का खतरा भी बना रहता है. आज हम आपको कुछ ऐसी बाते बताएंगे जो इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करते टाइम आपको ध्यान में रखनी चाहिए.

ओवरचार्जिंग से बचें ओवरचार्जिंग से ईवी बैटरी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है. ईवी बैटरी चार्ज करते समय, इसे 100 प्रतिशत तक चार्ज करने से बचें. अधिकांश ईवी में पाई जाने वाली लिथियम-आयन बैटरियां 30-80 प्रतिशत चार्ज रेंज में सबसे अच्छा काम करती

हैं. बैटरी को लगातार उसकी पूरी क्षमता तक चार्ज करने से बैटरी पर दबाव पड़ता है, इसलिए बैटरी को हमेशा 80 प्रतिशत तक चार्ज करने का प्रयास करें.

बैटरी डिस्चार्ज होने से बचाएं अगर आपको अच्छी रेंज चाहिए तो आपको बैटरी को लेकर थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. ईवी बैटरी को पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जब आप पूरी तरीके से डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज के लिए लगाते हैं तो शुरुआत में जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी लगती है, वह ज्यादा होती है. इससे आपके इलेक्ट्रिक चार्जिंग कॉस्ट में काफी फर्क देखने को मिलता है. इसलिए सलाह दी जाती है कि 10 से 15 परसेंट तक अगर आपकी बैटरी डाउन है तो उसे पूरी तरह से चार्ज कर सकते हैं।

बार-बार न करें चार्ज, अधिकतर लोग गलती करते हैं कि अपने इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी को बार-बार चार्ज करते हैं. बता दें कि ऐसा करने पर बैटरी की लाइफ घटती है. इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि बैटरी को कम से कम चार्ज करें. जब जरूरत हो तभी चार्ज करें इससे बैटरी लंबा चलेगी.

चलाने के बाद तुरंत न करें चार्जिंग राइडिंग के बाद अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग पर न लगाएं. क्योंकि मोटर को बिजली की सप्लाई करते समय लिथियम-आयन बैटरी बहुत गर्म हो जाती है, जिसका प्रभाव सीधे बैटरी की लाइफ पर पड़ता है. साथ ही वाहन की थर्मल समस्या भी बढ़ जाती है. इस बात का ख्याल रखें राइडिंग के कम से कम 30 मिनट की कूलिंग के बाद ही इसे चार्ज करें।

ब्रह्मा, विष्णु, महेश

पीके खुराना

हमारे देश में सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारक माना गया है। सनातन धर्म इन्हें परम तत्व की तीन अभिव्यक्तियों के रूप में स्वीकार करता है। विज्ञान कहता है कि इलैक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटोन की शक्ति के बिना किसी भी वस्तु का निर्माण सम्भव नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो प्रोटोन को ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु का अस्तित्व प्रोटोन की विधायी शक्ति के बिना प्रकट ही नहीं हो सकता।

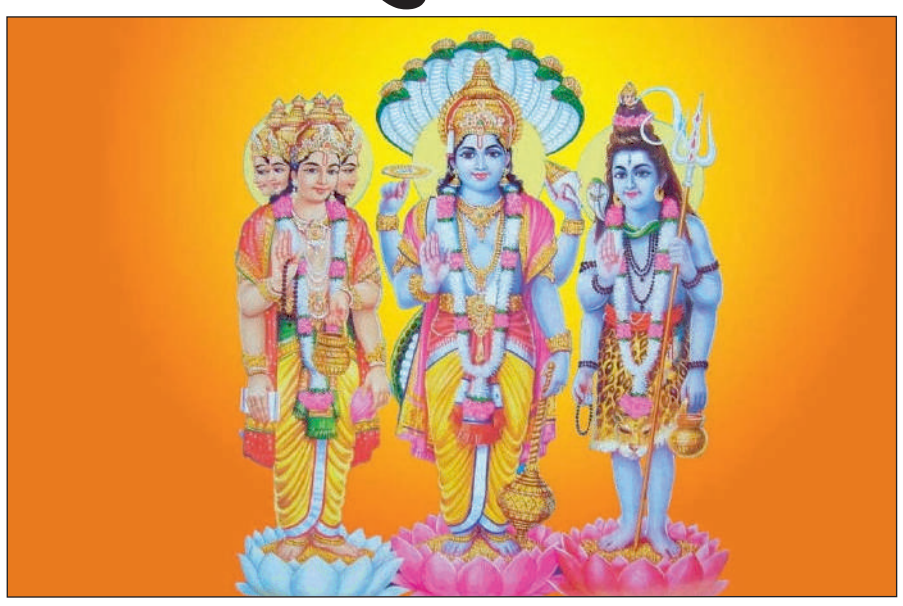

आज हममें से बहुत से लोग वास्तव में आध्यात्मिक होने के बजाय केवल आध्यात्मिक दिखने की परवाह करते हैं। निश्चित रूप से, एक फैंसी, आध्यात्मिक सोशल मीडिया पोस्ट लिखना आसान है, लेकिन वास्तव में उस उद्धरण पर खरा उतरना, उसे जीवन में उतारना, अपने व्यवहार में लाना कठिन हो सकता है। हमारे जीवन की असली सफलता इसी में है कि हम प्रेम का पाठ पढ़ लें, प्रेम के अढ़ाई अक्षरों को जीवन में उतार लें। यह एक मानसिक यात्रा है, यह मन के विचारों के बदलाव की यात्रा है, यह एक आंतरिक परिवर्तन है और इसके लिए कोई और दिखावा, या किसी और परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है'

हमारे देश में सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारक माना गया है। सनातन धर्म इन्हें परम तत्व की तीन अभिव्यक्तियों के रूप में स्वीकार करता है। विज्ञान कहता है कि इलैक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटोन की शक्ति के बिना किसी भी वस्तु का निर्माण सम्भव नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो प्रोटोन को ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु का अस्तित्व प्रोटोन की विधायी शक्ति के बिना प्रकट ही नहीं हो सकता। उसके प्रकटीकरण का मूल कारण विधायक है, इसीलिए ब्रह्मा जी को विधाता भी कहा गया है। विधाता प्रोटोन है। विधायक न हो तो किसी भी वस्तु की सृष्टि नहीं हो सकती, निर्माण नहीं हो सकता। प्रोटोन के बिना कोई भी वस्तु रूप-रंग, आकार-प्रकार धारण नहीं कर सकती, भौतिक रूप से प्रकट ही नहीं हो सकती। प्रत्येक वस्तु और प्राणी की तीन अवस्थाएं हैं : निर्माण, स्थिति और विनाश। स्थिति में परिवर्तन होता है। यदि परिवर्तन न हो तो उसका विनाश सम्भव नहीं। जिसके द्वारा वस्तु या प्राणी स्थित रहता है अथवा अपनी स्थिति बनाए रखता है, यह है स्थापक यानी भगवान विष्णु का प्रतिबिंब। विज्ञान की भाषा में हम जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं, अध्यात्म की दृष्टि से वह भगवान विष्ण के रूप की अभिव्यक्ति है।

शिव विध्वन्स है, इलैक्ट्रॉन है। यदि विध्वन्स न हो तो आविर्भूत वस्तु में परिवर्तन नहीं हो सकता, रूपान्तरण भी नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु भौतिक रूप में प्रकट होते ही परिवर्तित होने लगती है, उसमें रूपान्तरण होने लगता है जिसके फलस्वरूप वह नाश की ओर बढने लगती है। विध्वन्स की ओर उसका अस्तित्व उन्मुख हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन तीनों मौलिक अणुओं के नाम हैं जिन्हें धर्म ने विज्ञान को प्रदान किया है। ये तीन विश्व सृष्टि के आदि मौलिक देवता हैं। इनके न रूप हैं, न रंग हैं, न तो आकार-प्रकार हैं, तीनों अनाम हैं और अरूप हैं। फिर भी वे तीनों सनातन धर्म के मूलाधार हैं। विधायक न हो तो किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। विधायक जन्मदाता, ब्रह्मांड निर्माणकर्ता है। स्थापक न हो तो कोई भी वस्तु अपने अस्तित्व में नहीं रह सकती। अपनी स्थिति को उपलब्ध नहीं हो सकती। इसी प्रकार विध्वन्सक न हो तो वस्तु में परिवर्तन नहीं हो सकता और अन्त में उसका नाश नहीं हो सकता। परिवर्तन होना महत्वपूर्ण है। यदि कोई भी एक स्थिति बराबर बनी रहेगी और उसमें परिवर्तन नहीं होगा तो प्रकृति में विकृति उत्पन्न हो जाएगी, सृष्टि की मर्यादा भंग होने लगेगी। विकृति उत्पन्न न हो और सृष्टि की मर्यादा भी न भंग हो, इसके लिए परिवर्तन और विध्वन्स आवश्यक है। अस्तित्व अपने आपको तीन रूपों में अभिव्यक्त कर रहा है। तात्पर्य यह कि अस्तित्व की तीन अभिव्यक्तियों के योग से अस्तित्व निर्मित होता है। किसी भी अस्तित्व की अभिव्यक्ति के मूल में इन तीनों का योग समझना चाहिए। 'सहज संन्यासी' के रूप में इसीलिए हम यह मानते हैं कि इस ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर प्राणी और खुद हम भी इलैक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटोन के योग से ही बने हैं तो फिर फर्क कहां है? और अगर फर्क है ही नहीं तो किसी भी वस्तु या प्राणी से उपेक्षा कैसे हो सकती है, नफरत कैसे हो सकती है?

'सहज संन्यास मिशन' की ओर से यह बार-बार दोहराया जाता रहा है कि पूजा सिर्फ तभी पूजा है जब हम प्रेममय हो जाते हैं, देश, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र की बात छोडक़र हर व्यक्ति से प्रेम करने लगते हैं, बिना कारण प्रेम करने लगते हैं, और व्यक्ति से ही नहीं, हर वस्तु से प्रेम करने लगते हैं, हर जड़-चेतन जीवन का सम्मान करने लगते हैं, बिना कारण, बिना लालच, बिना किसी डर के। यह जीवनशैली अपना लें तो मन हमेशा प्रसन्न-प्रफुल्लित रहता है। जब हम प्रेममय हो जाते हैं तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं, किसी बात का गिला नहीं रह जाता, क्रोध नहीं रह जाता, पछतावा नहीं रह जाता, इन सब की जगह कृतज्ञता का भाव आ जाता है, समर्पण का भाव आ जाता है, सेवा का भाव आ जाता है। इस तरह हम अध्यात्म की कई सीढियां चढ़ जाते हैं। हम आध्यात्मिक होते हैं तो ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं। 'सहज संन्यास मिशन' के अनुगामी के रूप में हम सबका मानना है कि दुनिया माया नहीं है, जीवन सपना नहीं है। हम जीवित हैं, हमें एक शरीर मिला है और हम इस दुनिया में हैं, तो यह भी एक सच है, और इसे झुठलाया नहीं जाना चाहिए। दुनिया में रहकर दुनिया वालों से प्रेम करना, उनकी सेवा करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि हम सब के प्रति दया का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, जहां तक संभव हो, निस्वार्थ भाव से सहायता करें। हम खुद को बदलें, हमारे अंदर के परिवर्तन से ही सब कुछ बदलेगा। हमारा नजरिया बदलेगा तो हम बदलेंगे। हम बदलेंगे तो परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा, दुनिया बदलेगी। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगी, हमारी दुनिया नहीं बदलेगी। हमारे संपर्क में आने वाले लोग हमारी दुनिया हैं। हम बदल जाएंगे तो शायद हम उन लोगों में बदलाव ला सकेंगे जो हमारे संपर्क में आते हैं। हम ही नहीं बदले तो बाकी सब बदल भी जाए तो भी हमारे लिए वह बदलाव अर्थहीन ही रहेगा। समस्या यह है कि मार्केटिंग के इस युग में आध्यात्मिकता भी बिकाऊ हो गई है। हमें ऐसी बातें परोसी जा रही हैं जो सत्य प्रतीत होती हैं। हम झूठ को पकड़ लेते हैं, लेकिन अक्सर सच लगने वाले झूठ को, या सच और झूठ की मिलावट से बनी बातों के जाल में फंस जाते हैं।

सच तो यह है कि आध्यात्मिकता निरर्थक है यदि हम इसके बारे में बात करते हैं, सोचते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं करते। अध्यात्म व्यावहारिकता है, यह मांग करता है कि हम बात करें या न करें, पर अध्यात्म को व्यवहार में उतारें, उस पर अमल करें। पारंपरिक धर्म और नए युग की आध्यात्मिक शिक्षाओं दोनों ने दयालु और दयालु होने पर प्रकाश डाला है, लेकिन इन प्रणालियों ने 'आध्यात्मिक बनने की इच्छा रखने वाले' लोगों की एक सेना तैयार कर दी है। आज हममें से बहुत से लोग वास्तव में आध्यात्मिक होने के बजाय केवल आध्यात्मिक दिखने की परवाह करते हैं। निश्चित रूप से, एक फैंसी, आध्यात्मिक सोशल मीडिया पोस्ट लिखना आसान है, लेकिन वास्तव में उस उद्धरण पर खरा उतरना, उसे जीवन में उतारना, अपने व्यवहार में लाना कठिन हो सकता है। हमारे जीवन की असली सफलता इसी में है कि हम प्रेम का पाठ पढ़ लें, प्रेम के अढ़ाई अक्षरों को जीवन में उतार लें। यह एक मानसिक यात्रा है, यह मन के विचारों के बदलाव की यात्रा है, यह एक आंतरिक परिवर्तन है और इसके लिए कोई और दिखावा, या किसी और परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए ब्रह्मांड की हर वस्तु और हर प्राणी से प्यार ही अध्यात्म का एकमात्र स्वरूप है। बस इसे ही समझने की जरूरत है। सहज संन्यास भी श्रेष्ठ है।

संपादक की कलम से

केजरीवाल की भूमिका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को 'वैध' और 'न्यायसंगत' करार दिया है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) को अदालत ने तब करारा झटका दिया, जब उसने शराब नीति और कथित घोटाले में दोनों की संलिप्तता भी मानी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साक्ष्यों और दस्तावेजों के सौजन्य से कहा कि केजरीवाल साजिश में शामिल थे। उन्होंने 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर घूस भी मांगी थी। रिश्वत का पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया गया। उसकी मनी ट्रेरल भी स्पष्ट है। कानून की दृष्टि से मुख्यमंत्री को कोई विशेषाधिकार नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी चुनाव के समय पर न की जाती। ईडी ने जो सामग्री, तथ्य, ई-मेल और व्हाट्स एप चैट के ब्योरे अदालत के सामने रखे हैं, वे सही और पर्याप्त हैं। जांच एजेंसी ने सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की है। केजरीवाल गवाहों से 'क्रॉस' कर सकते हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने गंभीरता से यह टिप्पणी की है कि सरकारी गवाहों पर उंगली उठाना अदालत और न्यायाधीश पर आक्षेप लगाना है। अदालत का सरोकार संवैधानिक नैतिकता के प्रति है। अदालत पर कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं होता और न ही उसे चुनाव के समय, चुनावी टिकट और चुनावी बॉन्ड से कोई लेना-देना है। सरकारी गवाहों के बयान पीएमएलए और धारा 164 में न्यायाधीश के सामने लिए गए हैं। सरकारी गवाह का प्रावधान सैकड़ों साल पुराना है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि इन प्रावधानों का उपयोग केजरीवाल को फंसाने के लिए किया गया।

यह मामला ईडी और केजरीवाल के बीच का है। इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। केजरीवाल ने उच्च न्यायालय में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी, गलत करार दिया था, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इन टिप्पणियों के साथ केजरीवाल की अर्जी को खारिज कर दिया। केजरीवाल और 'आप' के सामने अब भी सर्वोच्च अदालत में इस फैसले को चुनौती देने का संवैधानिक विकल्प शेष है, लेकिन उच्च न्यायालय के स्तर पर यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि शराब नीति बनाने और उसकी आड़ में घूस मांगने के कथित अपराध में केजरीवाल भी संलिप्त थे। बेशक 'आप' के नेता और प्रवक्ता दलीलें देते रहें कि चवन्नी भी बरामद नहीं हुई है। केजरीवाल को फंसाना और जेल तक पहुंचाना अभी तक की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। भाजपा 'आप' को कुचल देना चाहती है, दिल्ली की सरकार गिराने के उसके मंसूबे हैं। 'आप' राजनीतिक स्तर पर कितने भी अभियान चलाए, लेकिन अदालत के सामने ठोस साक्ष्य हैं। उन्हें अदालत ने बुनियादी तौर पर स्वीकार भी किया है। हवाला ऑपरेटर्स के बयान भी मौजूद हैं। जिन्होंने घूस की राशि दी है, उनके बयान, ई-मेल, व्हाट्स एप चैट, बैठकों और मुलाकातों आदि के ब्योरे भी उपलब्ध हैं। केजरीवाल और 'आप' किस-किस को झुठलाने की कोशिश करेंगे। दरअसल केजरीवाल एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उनकी कानूनी टीम और अन्य सलाहकारों ने गलत सलाह दी। केजरीवाल को ईडी के 9 समन्स को खारिज नहीं करना चाहिए था। अब जो कानूनी निष्कर्ष सामने हैं, वे उच्च न्यायालय के हैं। किसी के खोखले आरोप नहीं हैं। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि यदि 'आप' का भ्रष्टाचार भी साबित हो गया और 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक के नाते केजरीवाल का अपराध भी साबित हो गया, तो चुनाव आयोग 'आप' की मान्यता भी रद्द कर सकता है।

'आप' के प्रवक्ताओं को शरत रेड्डी और 60 करोड़ रुपए के चुनावी चंदे और भाजपा की वाशिंग मशीन में धुल कर आरोपितों के पाक-साफ होने सरीखे तर्कों के अलावा कुछ और भी ठोस तर्क देने होंगे।

राय

हिमाचल की नसों में चिट्टा

हर जगह चिट्टे की है एक कहानी, सर्द चौकसी में पसीने की निगरानी। हिमाचल में चुनाव की सतर्क निगहबानी में नशा पकड़ा जा रहा है और इसी के संदर्भ में राजधानी शिमला को नसीहत भी मिल रही है। हालांकि चिट्टे की खेप का वजन महज 42.89 ग्राम ही हाथ लगा, लेकिन खबर बड़ी और हकीकत उससे बड़ी है। पंजाब के अक्स अब हिमाचल का गिरेबां पकड़ रहे हैं और धीरे-धीरे यह जहर हमारी युवा धमनियों में जहर घोल रहा है। तमाम चुनौतियों और युवा सवालों के बीच चिट्टे की धूनी जमाकर बच्चे जिंदगी का शतरंज खेल रहे हैं, लेकिन इस अपराध की कहानी में जिनके हाथ रंगे हैं, वे सुविधाजनक व्यवसाय की तरह देश को माप रहे हैं। शिमला में चिट्टे की चुटकी में समाज को हजारों चपेडें. और नशे के कारोबार में हमारी अपनी बदनाम गलियां बढ़ रही हैं। यह एक गहन नेटवर्क का खेल है, जहां अपराध पैदाइशी नहीं, बल्कि प्रस्तावित है। शिमला में भले ही नशे की मात्रा देखने में कम दिखाई दे रही है, लेकिन इसका चेहरा कातिल और पूंछ लंबी है। पंजाब के पूर्व मंत्री का बेटा अगर संलिप्त है, तो हिमाचल के कितने बेटों को इससे खतरा है, यह विस्तार से सोचना होगा। नशे में आमदनी, नशे में फैशन, नशे में पैशन और नशे में जिंदगी के वेकेशन तक पहुंच रही युवा पीढ़ी को बचाना अति आवश्यक है। पुडिया अब अपनी व्यवस्था करके चलती है और जहां कोरियर तक में पता सुनिश्चित है। हिमाचल नशे का डेस्टिनेशन क्यों बन रहा है, इसे समझने के लिए पुलिस ही काफी नहीं, समाज का रुतबा भी कमजोर हो रहा है। सदी के सबसे बड़े गुनाह में शरीक चिट्टा तय करके, तयशुदा कत्लगाह का सबसे भयावह चरित्र बन चुका है। ऐसे में पीढियां तब बचेंगी यदि समाज, अभिभावक, नीति नियंता, शासन-प्रशासन और प्रतिस्पर्धा का मौजूदा दौर इतना संवेदनशील बने कि हमारे अपने बच्चे न पीछे रहें और न ही उपेक्षित बनें। जीवन का बाई प्रोडक्ट अगर नशा बन गया, तो तहजीब की कालिख में हम सभी गुम हो जाएंगे। कानून का सुखद पहलू यह कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन दुखद पक्ष यह कि इस पकड़ा-पकड़ी में भी कोई बड़ा शिकार पकड़ में नहीं आता। चंद ग्राम के चिट्टे की बरामदगी में पुडिया अपना पूरा हुलिया नहीं बताती। हमारी अपनी नजरअंदाजी का मतलब यह भी कि समाज से परिवार तक स्वार्थ की तहों में संस्कार गुम हैं। ऐसे में कानून-व्यवस्था के दायरे में भले ही कुछ उदाहरण पेश हो जाएं, लेकिन नशे के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए समस्त तंत्र और सामाजिक मंत्र को एक साथ व्यवस्थागत उच्चारण ढूंढने पड़ेंगे। वर्तमान पीढ़ी को करियर की चक्की पर आखिर कब तक ऐसे पाठ्यक्रम पीसने पड़ेंगे, जो उसे सिर्फ शिक्षा की नुमाइश में विवशताएं ही दे रहा है। आश्चर्य यह कि नए स्कूलों में अग्रणी साबित हो रहे निजी संस्थान केवल विज्ञान तक ही सिमट गए हैं, जबकि व्यक्तित्व विकास के लिए कला की कक्षाओं या ह्यूमैनिटी अध्ययन के उच्च स्तरीय कक्ष विकसित करने होंगे। शिक्षा का स्तर व माहौल सामाजिक मूल्यों में विरक्तता पैदा कर रहा है। हम उपभोक्तावाद के ऐसे युग में प्रवेश कर गए हैं, जहां गली-मोहल्ले अंधे व बहरे साबित हो रहे हैं। ऐसे में खोखले वजूद पर जब हम भविष्य की उपलब्धियों का बोझ नहीं उठा पाते, तो इस दायित्व की परीक्षा में युवा पीढ़ी को धकेल देते हैं। जीवन की सहजता में उपयोगिता बढ़ाने के लिए समाज से सरकार तक को अपने फैसले बदलने पड़ेंगे। इसके अलावा पुलिस पेट्रोलिंग का ढर्रा, अध्ययन के आदर्श और सामाजिक प्रतिस्पर्धा की अस्तव्यस्तता को सुधारना पड़ेगा। चिट्टे की संस्कृति में सरोकारों की प्रतिबद्धता कहीं भटक जरूर रही है।

बेवफा की वफादारी

जमाना बेवफाओं के वफादार घोषित हो जाने का है। जिन लोगों ने दिन-दहाड़े आपके सपने चुरा कर उन्हें दुःस्वप्न बना दिया, वही अब सपनों का एक नया बायस्कोप बना कर निकले हैं, आपके गांव-गांव, गली-गली, अन्धभक्ति का कोई श्रद्धा गीत गाते हुए। मंशा अपने वोटों की सहायता से महानुभावों को फिर उसी कुर्सी पर बिठा देने की है, जो कभी पहले सिंहासन थी, आजकल जनसेवा का स्टूल कहलाती है। हमारी गलियों में जब बिजली कट अपनी तेजी दिखाते हैं, पावर कट अपना जुल्म दिखाते हैं, तो अपनी विजय घोषणाओं में सेंध लगती देख कर चौकीदार बने चोर अब 'जागते रहो' चिल्लाते हैं। भई, दल बदलुओं का जमाना है, कब कोई सेंधमार स्वांग बदल कर साधुवेष धारण कर आपको श्रद्धा से विनत होने के लिए कह दे कि बोलो भक्तो, ऊंचे स्वर में चिल्लाओ, 'जय-जय'। अगर कोई हमसे पूछने के लिए चला आए, यह किसकी जय-जय है, तो कह दो, तुम्हारी भी जय-जय और हमारी भी जय-जय। न पूछना किसी से कि जब आपके थर्मल प्लांटों के पुर्जे चार माह पहले बिगड़ गए थे, तो उसकी मरम्मत की ओर तब ध्यान क्यों नहीं दिया गया? 'दिया है, दिया है, बन्धु। मरम्मत के लिए स्वीकृति फाईल पर हाजिर है। बस अभी उसे निपटाने की बारी नहीं आई थी, कि यह कम्बख्त मानसून धोखा दे गया। भला यह कह के आदाब हैं कि जब आपको बरसना हो, तब तो बरसे नहीं, और अब बेमौसम बरसात करके जलथल पैदा कर दो।'

इससे वही बात हुई न, पिछली बार अपने चुनाव एजेंडे में हमारी अभागी धरती स्वर्ग लोक का वायदा किया था, फिर इसी स्थगित मानसून की तरह हमारी गलियों का रास्ता ही भूल गया। और अब जब चुनाव दुंदुभि बजे तो स्थगित मानसून के याद कर लेने की तरह हमारी गलियों में महानुभाव प्रगट हो गए, लो हमारे आंकड़े देख लो कि हमने तो अपने एजेंडे के पचासी प्रतिशत वायदे पूरे कर दिए। शेष पावर कट भगाने वाली इस लेट-लतीफी बारिश की वजह से रुके, अभी दूर कर देंगे। हमने सुना और प्रशंसा में तालियां बजा दीं, कैसे कह देते कि जनाब इस रास्ता भूली बारिश से कुछ नहीं होगा, जब तक कि इन लगातार बिगड़ते हुए थर्मल प्लांटों की स्थाई मरम्मत नहीं होती। उनको जुर्माना लगाने से क्या होगा, क्योंकि उससे अधिक बड़ा जुर्माना तो उद्योगों को इस लम्बी-चौड़ी पावर कट से लगा गया। उनका लाभ घाटे में बदल गया, तो निठुला हो सडक़ पर कामगार आया। नहीं, नहीं हमें सडक़छाप लोगों की बड़ी फिक्र है। आपके वोट डालने की तिथि से पहले सब वायदे पूरे हो जाएंगे। कसम आपके कल्याण की। बेशक भाषण में वायदों के पूरे होने की यह घोषणा बड़ी अच्छी लगती है। जैसे पार साल आपने कहा था, 'घर-घर रोजगार, अब नहीं रहेगा कोई बेकाम, बेरोजगार।' मजे की बात के इस वचन का उद्घोष उन बेकारों की भीड़ ने ही किया था, जो ठेके पर नारा लगाने का रोजगार पाकर आए थे। अब उसी रोजगार के बंटने के दिन फिर आ गए।

फिर दिहाडियों पर लगिए और विजय घोष कीजिए। महाकवि तो ठेले पर हिमालय लाद कर लाए थे, आपने तो ठेकों पर वायदों की पूर्ति की घोषणाएं लाद दीं, जय परिवर्तन के महाप्रभु। बन्धु, ठेके की इस कसौटी पर दमघोटू महंगाई का दाहकर्म कर देने का विजयघोष रखा जा सकता है। पहले तो क्रिकेट में ही खिलाडियों के शतक लगाने की घोषणाओं पर तालियां बजती थीं, अब तो ये पैट्रोल उत्पाद भी राज्य दर राज्य शतक लगाने लगे। चन्द सालों पहले कुछ नौजवान समूह स्वरोजगार की पताकाएं लहराते हुए हमारी सडक़ों पर भी निकले थे। उनका इरादा जगह-जगह पकौड़े तल कर बेकारी उन्मूलन और खाली हाथों को काम देने का था। फिर कम्बख्त यह तेल ही इतना महंगा हो गया कि अब दो सौ रुपए की छत से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं। पकौड़े कैसे तले जाएं बंधु?

सुरेश सेठ

विचार

थोपे गए चुनावों पर रायशुमारी

जागरूक मतदाताओं को ऐसे नेताओं के चरित्र एवं इरादों को परखना होगा जिनमें दूरदृष्टि, विजन और सकारात्मक नजरिए की घोर कमी होती है और जिनका एकमात्र लक्ष्य जीतना भर होता है। ऐसे नेता चुनावी प्रबंधन की बैसाखियों के बलबूते सत्तासुख भोगते हैं'

हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी 2024 को राज्यसभा चुनाव में हुए उलटफेर और क्रॉस वोटिंग के बाद से प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव हुए जुम्मा जुम्मा 15 महीने ही बीते थे कि कुर्सी की चाहत के चलते कांग्रेस के छह विधायकों द्वारा राज्यसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी से बगावत करते हुए और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान से उपजी परिस्थितियों के कारण विधायक पद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा इन 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव करवाने की घोषणा और इन बागी अयोग्य कांग्रेसी विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद हिमाचल के सत्ता समीकरण तो प्रभावित हुए ही हैं, अपितु पुनः उपचुनाव की नौबत आन पड़ी है। हाल फिलहाल इस शिक्षित मतदाताओं वाले राज्य में नैतिकता पर आधारित राजनीति पर भी बहस मुहाबिस जारी है और एक प्रकार से इन पूर्व विधायकों के आचरण की वजह से बेवजह थोपे गए उपचुनावों पर जनता जनार्दन की रायशुमारी महत्वपूर्ण रहेगी।

लोकतंत्र में जनता के मत को महत्वहीन समझ कर मात्र वोट बटोरने के बाद न केवल अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात करने और दलबदल कर पुनः चुनावों की नौबत पैदा कर अपने क्षेत्रों की आम जनता की विकास की चाहत को भी ठेंगा दिखाने का मामला कोई नई घटना नहीं है। इन पूर्व हो चुके विधायकों के अपने अपने क्षेत्रों में स्वागत समारोहों के आयोजनों के साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर माहौल को गरमाया है और आरोपों प्रत्यारोपों और मानहानि नोटिस भेजने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हिमाचल प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों के सम्भावित प्रत्याशियों ने अपनी अपनी मुश्कें कस ली हैं। इन छह विधानसभा सीटों के अलावा पूरे भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव के तहत आम चुनावों की भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा विधिवत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां धर्मशाला में 83 हजार 718, लाहौल स्पीति में 25 हजार 724, सुजानपुर में 76 हजार 830, बड़सर में 88 हजार 432, गगरेट में 84 हजार 887 और कुटलैहड़ के 87 हजार 857 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं हिमाचल में उपचुनाव के मतदान तारीख 01.06.2024 (शनिवार) को और मतगणना की तारीख 04.06.2024 (मंगलवार) रखी गई है। इसी प्रकार लोकसभा की चार सीटों के लिए कुल 5638422 मतदाताओं द्वारा 7990 मतदान केंद्रों में वोट डाले जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और आधुनिक संचार तकनीकी के जमाने में दूसरे विकसित देशों की तुलना में मिलने वाली सुविधाओं के दृष्टिगत अब भारतीय नागरिकों की उम्मीदें और अपेक्षाएं भी परवान चढ़ रही हैं।

2022 के विधानसभा चुनाव में भी हिमाचल के प्रबुद्ध एवं जागरूक मतदाताओं ने भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से छुटकारा मिले तथा विकास कार्य धरातल पर दिखलाई दें, की चाहत में मतदान किया था और उम्मीद लगाई थी कि कांग्रेस सरकार और विपक्षी दल के विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास का अलख जगाएंगे, लेकिन सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायकों की महत्वाकांक्षाओं के चलते प्रदेश के इन छह विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को पुनः उपचुनावों में वोटिंग करनी पड़ जाएगी, यह किसने सोचा था? अब तो जनता को वाकई जनार्दन की भूमिका में उतर कर दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। आम तौर पर देखा जाता है कि जब भी लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो पक्ष-विपक्ष के नेतागण विकास सम्बन्धी मुख्य मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकाकर व्यक्तिगत छींटाकशी और धर्म आधारित राजनीति पर उतर आते हैं और जनता जनार्दन से जुड़े हुए मुद्दे गौण होकर रह जाते हैं। अयोग्य ठहराय गए विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में दोबारा उपचुनावों के कारण आंशिक अस्थिरता का संकट झेल रही कांग्रेस सरकार द्वारा अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए बहाल की गई पुरानी पेंशन प्रणाली के बने रहने पर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तो विधानसभा में ललकारते हुए कर्मचारियों को चुनाव लड़ लेने की भी सलाह दे डाली थी। माननीयों द्वारा खुद के लिए पेंशन और कर्मचारियों के लिए मामूली पेंशन की वकालत के मुद्दे पर कर्मचारियों का इन छह सीटों के उपचुनाव में क्या रवैया रहता है, यह भी एक विचारणीय विषय रहेगा। क्या कर्मचारी वर्ग इन छह सीटों को पुनः कांग्रेस की झोली में डालकर अपनी पुरानी पेंशन को सुरक्षित करने की दिशा में एकजुट रहेंगे?

आम नागरिकों के पास पांच वर्षों के बाद मौका आता है जब वे नाकाबिल जनप्रतिनिधियों को बाहर का रास्ता दिखाकर ईमानदार, सुयोग्य, कर्मठ, मेहनती और स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को विजेता बना सकते हैं, लेकिन इस बार हिमाचल में हो रहे उपचुनाव की वजह से यह मौका जल्दी ही आन पड़ा है। लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत आज जरूरत इस बात की भी है कि सरकारें एक नए राष्ट्रीय एजेंडे को सामने लाएं और अपने नागरिकों में एक राष्ट्रीय चरित्र को विकसित करने की चुनौती को स्वीकार करें जहां विकसित भारत की अवधारणा सर्वोपरि हो। चरित्र निर्माण की भावना चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर भी लागू होती है। ऐसे जनप्रतिनिधि किस काम के जो जनसेवा के बजाय महज अपने फायदे के लिए मतदाताओं पर पुनः चुनाव लाद दें, मतदाताओं को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। जागरूक मतदाताओं को ऐसे नेताओं के चरित्र एवं इरादों को परखना होगा जिनमें दूरदृष्टि, विजन और सकारात्मक नजरिए की घोर कमी होती है और जिनका एकमात्र लक्ष्य जीतना भर होता है। ऐसे नेता महज चुनावी प्रबंधन की बैसाखियों के बलबूते सत्तासुख भोगते हैं और आम जनता ठगी से वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है।

अनुज आचार्य

ईद के दिन जारी हुए पेट्रोल-डीजल की कीमतें, चेक करें अपने शहर के लेटेस्ट रेट

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने ईद-उल-फितर (Eid-Ul-Fitr 2024) के मौके पर पेट्रोल-डीजल के प्राइस को अपडेट कर दिया है। आज भी गाड़ीचालकों को राहत है। इसका मतलब है कि देश के सभी शहरों में फ्यूल के दाम (Fuel Price Today) जस के तस बने हुए हैं।

देश के सभी शहरों में पेट्रोल-डीजल के रेट (Petrol-Diesel Price) अलग हैं। ऐसे में आपको गाड़ी की टंकी फुल करवाने से पहले लेटेस्ट रेट जरूर चेक करना चाहिए। आइए, जानते हैं कि पेट्रोल-डीजल के रेट आपके शहर में कितनी है।

महानगरों में क्या है पेट्रोल- डीजल के दाम

HPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, आज (8, अप्रैल 2024) पेट्रोल- डीजल की कीमतें इतनी रहेंगी-

राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपये और डीजल की कीमत 87.66 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है।

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.13 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है।

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.93 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.74 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है।

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.73 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.32 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है।

बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर और डीजल 85.92 रुपये प्रति लीटर है।

हैदराबाद समेत अन्य शहरों में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट

नोएडाः पेट्रोल 94.81 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.94 रुपये प्रति लीटर

गुरुग्रामः पेट्रोल 95.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.03 रुपये प्रति लीटर

चंडीगढ़ः पेट्रोल 94.22 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.38 रुपये प्रति लीटर

हैदराबादः पेट्रोल 107.39 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.63 रुपये प्रति लीटर

जयपुरः पेट्रोल 104.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.34 रुपये प्रति लीटर

पटनाः पेट्रोल 105.16 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.03 रुपये प्रति लीटर

लखनऊः पेट्रोल 94.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.74 रुपये प्रति लीटर

संकट में चीन की अर्थव्यवस्था, फिच ने स्थिर से नकारात्मक की क्रेडिट रेटिंग

नई दिल्ली। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने सार्वजनिक ऋण और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि पर चिंताओं का हवाला देते हुए बुधवार को चीन के क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को स्थिर से नकारात्मक कर दिया।

फिच ने तर्क दिया कि हाल के वर्षों में व्यापक राजकोषीय घाटे और बढ़ते सरकारी ऋण ने राजकोषीय भंडार को नष्ट कर दिया है। उसका यह भी कहना है कि रियल एस्टेट के साथ-साथ दूसरे सेक्टर में जोखिम के अनुमान है, जिसके चलते चीन की सॉवेरन क्रेडिट रेटिंग (Sovereign Credit Rating) को वह फिलहाल निगेटिव कर रहा है।

पिछले काफी समय से चीन का रियल एस्टेट सेक्टर पर काले बादल मंडरा रहे हैं। यही कारण है कि चाइना की इकोनॉमी प्रॉपर्टी आधारित ग्रोथ से दूर होती जा रही है। इन्हीं जोखिम के चलते रेटिंग एजेंसी फिच ने चीन की सॉवेरन क्रेडिट रेटिंग को स्थिर से नकारात्मक कर दिया है। हालांकि ये दिलचस्प है कि चीन शुरुआत से रियल एस्टेट सेक्टर को स्टेबल डेवलपमेंट मॉडल के रूप में पेश करता आया है, जो अब अनिश्चित आर्थिक संभावनाओं से जूझ रहा है।

लगातार बढ़ रहा चीन का खर्च

फिच ने अपनी रिपोर्ट में यह भी हवाला दिया है चीन का खर्च लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते खर्च को देखते हुए चीन ने अपना राजकोषीय बफर्स को भी खत्म कर दिया है। फिच का मानना है कि आने वाले दिनों विकास परियोजनाओं के लिए चीन के कर्ज में बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है।

समाचार एजेंसी एएनआई मुताबिक, चीनी सरकार आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए राजकोषीय खर्च को प्रोत्साहन दे रही है। फिन ने यह भी अनुमान लगाया है कि सामान्य सरकारी घाटा 2024 में सकल घरेलू उत्पाद का 7.1 प्रतिशत हो जाएगा, जो 2023 में 5.8 प्रतिशत था।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी से भारत को हो रहा फायदा, मिल रहा डिजिटल पेमेंट का बेनिफिट

संयुक्त राष्ट्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट एट ए क्रॉसरोड रिपोर्ट में कहा गया है कि मल्टी नेशनल कंपनियां भारत में रूचि दिखा रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर निवेश नरम रहने की उम्मीद है। इसके विपरीत दक्षिण एशिया विशेष रूप से भारत में निवेश मजबूत बना हुआ है। यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत में दिलचस्पी दिखा रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी से भारत को फायदा हो रहा है। ये कंपनियों भारत को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण रणनीतियों के संदर्भ में वैकल्पिक विनिर्माण आधार के रूप में देखती हैं।

मल्टी नेशनल कंपनियों की पसंद

यह इस बात को भी उजागर करती है कि देश में निवेश मजबूत बना हुआ है। यह बात संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख रिपोर्ट में कही गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट : फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट एट ए क्रॉसरोड में कहा गया है कि विकास वित्तपोषण अंतर को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तपोषण जुटाने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। यह सालाना 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, जो कोविड महामारी से पहले 2.5 ट्रिलियन डालर था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर निवेश नरम रहने की उम्मीद है। इसके विपरीत दक्षिण एशिया विशेष रूप से भारत में निवेश मजबूत बना हुआ है। भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती रुचि से लाभ मिल रहा है।

डिजिटल पेमेंट का मिल रहा फायदा

अधिकांश विकासशील देशों में संभावनाएं कमजोर हैं। धीमी वृद्धि के बीच ऋण का उच्च स्तर राजकोषीय स्थिति को बाधित कर रहा है, जिससे सरकारों के लिए उधार लेना और निवेश करना कठिन हो गया है।

संघर्षों की वजह से अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में निवेश में बाधा आ रही है। इसके साथ ही भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का भी फायदा मिला है।

डिजिटल भुगतान पर बढ़ा देशवासियों का भरोसा; UPI से अगस्त में हुए 10 अरब से ज्यादा लेनदेन

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार 30 अगस्त को यूपीआइ लेनदेन का आंकड़ा 10.24 अरब हो गया। इन लेनदेन का मूल्य 1518456.4 करोड़ रुपये रहा। जुलाई में यूपीआइ लेनदेन की संख्या 9.96 अरब थी जबकि जून में यह 9.33 अरब थी। अगस्त 2021 में यूपीआई के जरिए लेनदेन का आंकड़ा केवल 3.5 बिलियन था जो दो वर्षों में लगभग तीन गुना बढ़ चुका है।

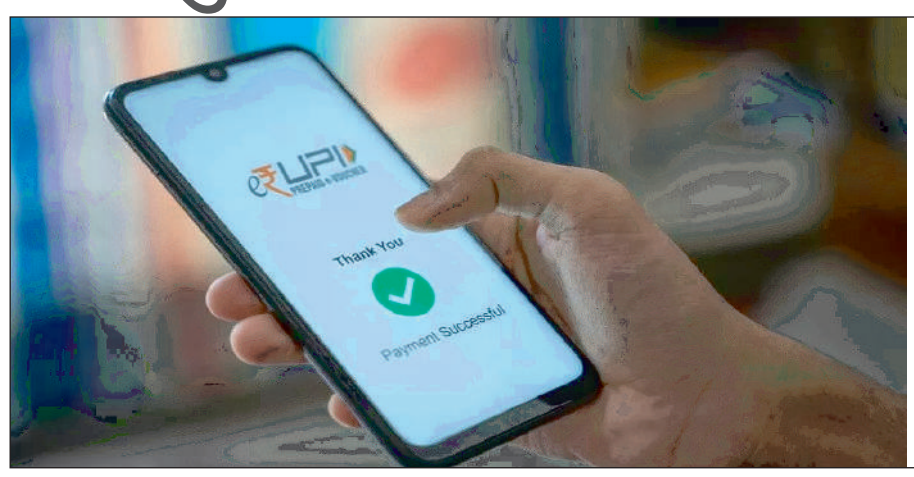

अगस्त 2021 में यूपीआई के जरिए लेनदेन का आंकड़ा केवल 3.5 बिलियन था, जो दो वर्षों में लगभग तीन गुना बढ़ चुका है। हमारे देश में अब ज्यागदात व्यापारी यूपीआई के जिए लेनदेन पर भरोसा दिखा रहे हैं। आज के समय करोड़ों की कमाई करने वाले व्यापारी हो या सब्जी बेचने वाले छोटे-मंझोले दुकानदार, सभी यूपीआई के जरिए लेनदेन कर रहे हैं।

अगस्त 2021 में यूपीआई के जरिए लेनदेन का आंकड़ा केवल 3.5 बिलियन था, जो दो वर्षों में लगभग तीन गुना बढ़ चुका है। हमारे देश में अब ज्यागदात व्यापारी यूपीआई के जिए लेनदेन पर भरोसा दिखा रहे हैं। आज के समय करोड़ों की कमाई करने वाले व्यापारी हो या सब्जी बेचने वाले छोटे-मंझोले दुकानदार, सभी यूपीआई के जरिए लेनदेन कर रहे हैं।

गौरतलब है कि 35 से ज्यादा देश अब भारत की यूपीआई तकनीक को अपनाना चाहते हैं। जापान उन देशों में शामिल है जिन्होंने हाल ही में यूपीआई को अपनाने में रुचि व्यक्त की है।

डिजिटल भुगतान पर बढ़ा देशवासियों का भरोसा

साल 2016-17 मे नोटबंदी के दौरान भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया। साल 2016 में मोदी सरकार ने UPI-BHIM लॉन्च किया था। नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर लोगों ने डिजिटल भुगतान पर भरोसा किया।

इसके बाद कोविड महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान के जरिए देश के ज्यादातर लोग पैसों के भुगतान के लिए कैश की जगह यूपीआई को चुना और आज के समय हर तरफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यूपीआई पर भारतीयों का अटूट भरोसा है।

समंदर पर बने रेलवे के इस ब्रिज को देनी पड़ रही 'अग्नि परीक्षा', इस मामले में है भारत का पहला पुल

क या आप जानते हैं कि नए पंबन ब्रिज को एक तरह की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। जी हां भारत के पहले 'वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज' के लिए 'घुमाव' बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। इस पुल को बनाने के लिए रेलवे के समक्ष पहले ही तकनीकी और अशांत समुद्र की चुनौती थी। 2.08 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने निर्माण के क्षेत्र में कई कीर्तिमान बनाए हैं। चाहे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने हों या फिर कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज। कन्याकुमारी का पंबन ब्रिज (Pamban Bridge) भी उसी का एक नमूना है। लेकिन पुराने पंबन ब्रिज का समय लगभग पूरा हो चला है, ऐसे में एक नए ब्रिज का निर्माण किया गया है। यह ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना होने वाला है। बता दें कि पंबन ब्रिज भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला पुल है।

क्या आप जानते हैं कि नए पंबन ब्रिज को एक तरह की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। जी हां, भारत के पहले 'वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज' के लिए 'घुमाव' बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। इस पुल को बनाने के लिए रेलवे के समक्ष पहले ही तकनीकी और अशांत समुद्र की चुनौती थी।

2.08 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) कर रहा है। इस पुल के वर्टिकल लिफ्ट यानी उठाने वाला हिस्से को ऊपर ले जाने वाले 'लिफ्ट स्पैन' का आकार 72.5 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा है और इसका वजन 550 टन है। आरवीएनएल को इस हिस्से को रामेश्वरम तट से 450 मीटर दूर समुद्र तक पहुंचाने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

> **2.08 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) कर रहा है। इस पुल के वर्टिकल लिफ्ट यानी उठाने वाला हिस्से को ऊपर ले जाने वाले 'लिफ्ट स्पैन' का आकार 72.5 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा है और इसका वजन 550 टन है। आरवीएनएल को इस हिस्से को रामेश्वरम तट से 450 मीटर दूर समुद्र तक पहुंचाने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।**

आरवीएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''हमने 10 मार्च को इस लिफ्ट स्पैन को आगे बढ़ाना शुरू किया और आज तक, हम 550 टन के लिफ्ट स्पैन को पुल के केंद्र की ओर 80 मीटर आगे बढ़ा चुके हैं। सबसे बड़ी चुनौती पुल का 2.65 डिग्री घुमाव है। अगर यह सीधा होता तो हम इसे तेजी से निश्चित स्थान पर पहुंचा पाते।''

उन्होंने कहा कि अलाइनमेंट से जुड़े कई बदलावों के कारण घुमावदार आकार को रखना आवश्यक था। अधिकारी ने बताया कि लिफ्ट स्पैन को उसके अंतिम बिंदु तक ले जाने का काम मई के अंत तक पूरा हो जाएगा और इसे अभी भी 370 मीटर आगे पहुंचाया जाना बाकी है। अधिकारी ने बताया कि एक बार जब घुमावदार हिस्से को पार कर लिया जाएगा तो फिर और तेजी से काम हो सकेगा।

कंपनी ने इस ब्रिज को शुरू करने के लिए 30 जून की समय सीमा तय की है और अधिकारियों का कहना है कि इस डेडलाइन पर काम खत्म करने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है।

ग्रीन और ऑर्गेनिक के नाम पर भ्रामक प्रचार पड़ सकता है भारी, इन विज्ञापनों पर होगी कार्रवाई

आजकल बाजार में ग्रीन व ऑर्गेनिक या बायोडिग्रेडेबल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर उत्पाद बेचने का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। भ्रामक विज्ञापन के जरिए उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार ग्रीनवाशिंग कानून ला रही है। ग्रीनवाशिंग का मतलब है कि पर्यावरण अनुकूल नहीं होने के बावजूद ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ग्रीन क्लीन आर्गेनिक इको फ्रेंडली कार्बन न्यूट्रल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना।

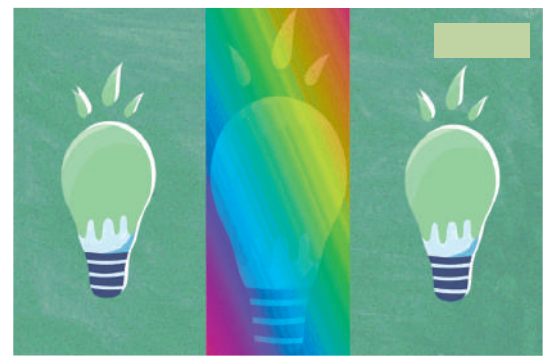

नई दिल्ली। आजकल बाजार में ग्रीन व ऑर्गेनिक या बायोडिग्रेडेबल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर उत्पाद बेचने का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई बार ग्रीन पैकेजिंग का भी दावा किया जाता है, ताकि ग्राहक आकर्षित हो सके। लेकिन इनमें से कई ऐसे उत्पाद होते हैं जो असलियत में ग्रीन या ऑर्गेनिक नहीं होते हैं या फिर आंशिक रूप से होते हैं। इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापन के जरिए उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार ग्रीनवाशिंग कानून ला रही है।

ग्रीनवाशिंग क्या है?

ग्रीनवाशिंग का मतलब होता है कि पर्यावरण अनुकूल नहीं होने के बावजूद ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ग्रीन, क्लीन, ऑर्गेनिक, इको फ्रेंडली, कार्बन न्यूट्रल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। अगर कोई कंपनी अपने उत्पाद पर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेगी तो उन्हें क्यूआर कोड या अन्य माध्यम से अपने दावे की जानकारी ग्राहकों को देनी पड़ेगी।

जल्द लागू होगा नियम

उपभोक्ता मामले का मंत्रालय के इस दिशा निर्देश को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर उनके उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध तक लगाया जा सकता है। दिशा निर्देश के मुताबिक कई बार उत्पाद पर लिखा होता है कि उनकी पैकेजिंग 100 प्रतिशत रिसाइकल्ड मटेरियल से की गई है, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं होता है। ऐसे में उत्पाद पर यह जानकारी देनी होगी किस सर्टिफिकेट के आधार पर वह इस बात का दावा कर रहे हैं।

इन विज्ञापनों पर होगी कार्रवाई

कई बार कपड़े धोने वाले उत्पाद पर लिखा होता है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केमिकल मुक्त। इस प्रकार के विज्ञापन को भी भ्रामक माना जाएगा क्योंकि इसका मतलब हुआ कि धोने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उत्पाद हानिकारक है। ग्रीन व ऑर्गेनिक का दावा करने से पहले उन्हें अधिकृत एजेंसियों से उत्पाद का सत्यापन कराना होगा और उपभोक्ता को भी इसे बताना होगा। हाथ धोने वाले उत्पाद पर लिखा होता है बायोडिग्रेडेबल। लेकिन असल में प्लास्टिक की बोतल में डाली गई लिक्विड बायोडिग्रेडेबल है न कि बोतल। ऐसे में यह स्पष्ट करना होगा कि सिर्फ लिक्विड बायोडिग्रेडेबल है, वह बोतल नहीं।

देश में भीषण गर्मी और हीटवेव को लेकर केंद्र सरकार सतर्क, पीएम मोदी ने स्थिति से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीट वेव से को लेकर स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की। गर्मी अब धीरे-धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है। वहीं बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा प्रधान मंत्री को आगामी गर्म मौसम के मौसम (अप्रैल से जून) के पूर्वानुमान सहित अप्रैल से जून 2024 की अवधि के लिए तापमान दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी गई।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीट वेव से को लेकर स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की। गर्मी अब धीरे-धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है। वहीं, बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा प्रधान मंत्री को आगामी गर्म मौसम के मौसम (अप्रैल से जून) के पूर्वानुमान सहित अप्रैल से जून 2024 की अवधि के लिए तापमान दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी गई।

देश के अधिकांश हिस्सों में बढ़ेगी गर्मी

देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है, विशेष रूप से मध्य भारत में इसकी उच्च संभावना है। पीएमओ ने कहा कि बैठक में आवश्यक दवाओं, तरल पदार्थ, आइस पैक, ओआरएस और पीने के पानी के संदर्भ में स्वास्थ्य क्षेत्र में तैयारियों की समीक्षा की गई।

पीएम के अलावा ये लोग भी बैठक में रहे मौजूद

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकार के सभी अंगों और विभिन्न मंत्रालयों को इस पर तालमेल के साथ काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी के साथ-साथ जागरूकता सृजन पर भी जोर दिया।

उन्होंने जंगल की आग का त्वरित पता लगाने और उसे बुझाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने भाग लिया।

NASA में एक बार फिर बजा भारतीयों का डंका, भारतवंशी वैज्ञानिक ने किया सूर्य ग्रहण में नासा के मिशन का नेतृत्व

पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान नासा के मिशन का नेतृत्व भारतवंशी वैज्ञानिक आरोह बड़जात्या ने किया। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने गत आठ अप्रैल को पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान ग्रह के एक हिस्से में क्षण भर के लिए सूर्य की रोशनी कम होने पर पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए तीन राकेट लांच किए थे।

मुंबई। अभी हाल ही में पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान नासा के मिशन का नेतृत्व भारतवंशी वैज्ञानिक आरोह बड़जात्या ने किया। आरोह ने 2001 में अमेरिका जाने से पहले देश के कई शहरों में पढ़ाई की थी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने गत आठ अप्रैल को पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान ग्रह के एक हिस्से में क्षण भर के लिए सूर्य की रोशनी कम होने पर पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए तीन राकेट लांच किए थे।

आरोह बड़जात्या ने किया नासा के मिशन का नेतृत्व

नासा ने बताया कि मिशन का नेतृत्व फ्लोरिडा की एम्ब्री-रिडल एयरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग भौतिकी के प्रोफेसर आरोह बड़जात्या ने किया। आरोह ने मिशन के बाद इंटरनेट मीडिया पोस्ट के माध्यम से साथी वैज्ञानिकों, एम्ब्री-रिडल एयरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी के साथियों एवं नासा का आभार जताया।

भारत में हुई है पढ़ाई

केमिकल इंजीनियर अशोक कुमार बड़जात्या व गृहिणी राजेश्वरी के पुत्र आरोह ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, पिलानी, सोलापुर में पूरी की और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सोलापुर के वालचंद इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी से की। उनकी बहन अपूर्वा बड़जात्या ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री व स्पेसक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंटेशन में पीएचडी की है।

कौन हैं लिंडी कैमरून जो होंगी भारत में ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त, जानिए कब संभालेंगी अपना कार्यभार

ब्रिटेन ने लिंडी कैमरून (Lindy Cameron) को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह एलेक्स एलिस का स्थान लेंगी। भारत में ब्रिटेन के दूतावास ने गुरुवार को जारी बयान में कहा लिंडी कैमरून को एलेक्स एलिस के उत्तराधिकारी के रूप में भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है।एलिस को कोई अन्य राजनयिक जिम्मेदारी दी जाएगी। बता दें कि कैमरून इस महीने अपना कार्यभार संभालेंगी।

नई दिल्ली। ब्रिटेन ने लिंडी कैमरून को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह एलेक्स एलिस का स्थान लेंगी। लिंडी कैमरून की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ब्रिटेन और भारत काफी समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत में जुटे हैं। भारत में ब्रिटेन के दूतावास ने गुरुवार को जारी बयान में कहा, लिंडी कैमरून को एलेक्स एलिस के उत्तराधिकारी के रूप में भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है।

एलिस को दी जाएगी कोई अन्य राजनयिक जिम्मेदारी

एलिस को कोई अन्य राजनयिक जिम्मेदारी दी जाएगी। नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि कैमरून इस महीने अपना कार्यभार संभालेंगी। कैमरून 2020 से ब्रिटेन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य कर रही हैं। वह ब्रिटेन के उत्तरी आयरलैंड कार्यालय की महानिदेशक की जिममेदारी भी निभा चुकी हैं। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के तौर पर अपनी नियुक्ति को लेकर लिंडी कैमरून ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत में अगला ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त होने पर बेहद गर्व है। महान विरासत के लिए एलिक्स एलिस को धन्यवाद।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन प्राधिकार से मांग , हमें स्वस्थ लोकतंत्र और पारदर्शी चुनाव चाहिए: भाजपा

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुवनेश्वर। भारतीय चुनाव आयोग के एक्शन के बाद कुछ वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बदल दिया गया है। 9 साल से मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात पुलिस आईजी डी.एस.कुट्टे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और सरकारी अधिकारियों के माध्यम से सत्तारूढ़ बीजेडी के पक्ष में वोट चुराने का अवैध काम कर रहे हैं। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। दूसरी ओर, सत्तारूढ़ बिजेड़ी सरकारी शक्ति और बल का दुरुपयोग करके वोट हथियाने के नापाक इरादे से बाज नहीं आई। पिछले 2019 के आम चुनाव में मुख्यमंत्री की सुरक्षा के प्रभारी रहे तत्कालीन पुलिस डीआइजी आशीष सिंह प्रोन्नति के बाद अन्यत्र पदस्थापित हो गये । इस बात के बहुत से सबूत हैं कि चुनाव प्रबंधन ने चुनाव में सत्तारूढ़ बिजेड़ी के पक्ष में काम किया। चुनाव आयोग की बर्खास्तगी के बाद राज्य सरकार ने आईजी पद पर प्रोन्नत श्री सिंह को एक बार फिर मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी है । इसी प्रकार, उत्तरान्छल पुलिस के आईजी श्री सत्यब्रत भोई भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के लिए काम कर रहे हैं। प्रशासन में सत्तारूढ़ बिजेड़ी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का पक्षपात स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। राज्य के मुख्य प्रवक्ता श्री सज्जन शर्मा के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव अधिकारियों से शिकायत की है कि इससे राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होंगे।

सत्तारूढ़ बीजू जनता दल चुनाव जीतने के लिए सरकारी अधिकारियों को पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करवा रहा है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मोबाइल फोन में चोरी के सिम डालकर लोगों को धमका रहे हैं और उन्हें बिजेड़ी को वोट देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भाजपा ने इस तरह की गड़बड़ियों के लिए बार-बार मुख्य चुनाव अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है। चुनाव जीतने की चाहत में राज्य सरकार सारे नियम-कानून भूल रही है । श्री शर्मा ने कहा कि यह पूर्णत दंडनीय अपराध है ।

कर्नाटक में अब तक 146 करोड़ की शराब, 45.67 करोड़ की नकदी जब्त; निष्पक्ष-स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए आयोग बरत रहा सख्ती

चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सख्ती बरत रहा है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के लिए आयोग के निर्देश पर नकदी शराब और मतदाताओं को प्रलोभित करने वाले साधनों पर शिकंजा कसा जा रहा है।कर्नाटक में 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 146 करोड़ मूल्य की शराब और 45 .67 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की जा चुकी है।

बेंगलुरु। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सख्ती बरत रहा है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के लिए आयोग के निर्देश पर नकदी, शराब और मतदाताओं को प्रलोभित करने वाले साधनों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कर्नाटक में 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 146 करोड़ मूल्य की शराब और 45.67 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की जा चुकी है।

भारी मात्रा में मुफ्त बांटे जाने वाला सामान जब्त

कर्नाटक की 28 सीटों पर दो चरण में 26 अप्रैल और सात मई को आम चुनाव होना है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि उड़नदस्तों, निगरानी दलों और पुलिस की टीमों ने 45.67 करोड़ की नकदी, 9.70 करोड़ मूल्य के मादक पदार्थ, 10.81 करोड़ का सोना और 7.73 करोड़ रुपये की मुफ्त में बांटे जाने वाला सामान जब्त किया है।

आंध्र प्रदेश में 100 करोड़ रुपये की नकदी व शराब जब्त

इधर, आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने गुरुवार को बताया कि आंध्र प्रदेश में 16 मार्च से अब तक 100 करोड़ रुपये की नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं व मुफ्त में बांटे जाने वाले सामान को जब्त किया है।

मिजोरम में छह करोड़ की अवैध शराब व ड्रग्स जब्त

आम चुनाव से पहले मिजोरम पुलिस अब तक छह करोड़ रुपये की अवैध शराब और ड्रग्स जब्त कर 94 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अवैध शराब से जुड़े 61 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया और 51 मामले दर्ज किए गए। वहीं ड्रग्स के मामले में 25 मामले दर्ज कर 33 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

मार्केट में इस दिन छप कर आएंगी तीसरी और छठी क्लास की नई किताबें, NCERT ने किए बड़े बदलाव

NCERT ने फिलहाल तीसरी कक्षा की गणित सहित चार विषयों की नई पाठ्य पुस्तकों के ई-वर्जन को जारी किया है। इन पाठ्य पुस्तकों के नाम भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम पर रखे गए हैं। इनमें वीणा संतूर सितार व बांसुरी जैसे नाम हैं। स्कूलों के लिए तैयार की गई इन किताबों के कवर पेज पर चंद्रयान सहित देश का गौरव बढ़ाने वाले पहलुओं को भी जगह दी गई है।

नई दिल्ली। स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई जाने वाले नई पाठ्य पुस्तकें बच्चों के लिए न सिर्फ रुचिकर, बल्कि भारतीयता के रंग में भी पूरी तरह रंगी हुई होंगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने फिलहाल तीसरी कक्षा की गणित सहित चार विषयों की नई पाठ्य पुस्तकों के ई-वर्जन को जारी किया है।

इन पाठ्य पुस्तकों के नाम भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम पर रखे गए हैं। इनमें वीणा, संतूर, सितार व बांसुरी जैसे नाम हैं। स्कूलों के लिए तैयार की गई इन किताबों के कवर पेज पर चंद्रयान, अग्नि मिसाइल सहित देश का गौरव बढ़ाने वाले पहलुओं को भी जगह दी गई है।

तीसरी कक्षा की किताबों में बदलाव

एनसीईआरटी ने तीसरी कक्षा की जो चार विषयों की नई पुस्तकें जारी है, उनमें गणित, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की पाठ्य पुस्तकें शामिल है। इस कक्षा की बाकी पुस्तकें जिनमें आर्ट और फिजिकल एजुकेशन भी अगले दस दिनों के भीतर जारी हो जाएगी। इस दौरान हिंदी की पुस्तक को वीणा, अंग्रेजी की पुस्तक को संतूर, उर्दू की पुस्तक को सितार और आर्ट एजुकेशन की पुस्तक को बांसुरी जैसे नाम दिए गए हैं। एनसीईआरटी का दावा है कि छठी कक्षा की नई पाठ्य पुस्तकें भी लगभग तैयार हो चुकी हैं। इन्हें भी जल्द जारी कर दिया जाएगा।

15 मई तक आएंगी किताबें

15 मई तक तीसरी और छठी कक्षा की सभी पाठ्य पुस्तकें छप कर आ जाएंगी। तीसरी और छठी कक्षा की यह सभी नई पाठ्य पुस्तकें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप तैयार की गई हैं। इस साल नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के प्रीपेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्तर की पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत ही तीसरी व छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई है। हालांकि, नौवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकें इस साल नहीं तैयार हो पाई हैं। माना जा रहा है कि इनमें अभी और समय लगेगा। करीब साल भर का और समय लग सकता है। स्कूलों के नए नेशनल कैरीकुलम फ्रेमवर्क के तहत अगले साल यानी 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में इन सभी स्तरों के अगली कक्षाओं यानी चौथी, पांचवीं, सातवीं कक्षाओं की किताबें आएगी।

नई किताबों से पहले छात्रों को करना होगा ब्रिज कोर्स

स्कूलों में तीसरी और छठी कक्षा के छात्रों के नए शैक्षणिक सत्र से नई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से पहले एक ब्रिज कोर्स करना होगा। एनसीईआरटी ने इस ब्रिज कोर्स को तैयार कर जारी कर दिया है। तीसरी कक्षा का ब्रिज कोर्स करीब एक सप्ताह का होगा, जबकि छठी कक्षा का ब्रिज कोर्स करीब एक महीने का होगा।

इस दौरान छात्रों को पुराने पाठ्यक्रम से नए पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार करने के लिए जरूरी पढ़ाई कराई जाएगी। एनसीईआरटी के मुताबिक केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सीबीएसई स्कूलों से जुड़े चु¨नदा शिक्षकों को 15 और 16 अप्रैल को ब्रिज कोर्स और नए पाठ्यक्रम को पढ़ाने से जुड़ा एक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

क्या कहते हैं एनसीईआरटी निदेशक

एनसीईआरटी निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा 'नए शैक्षणिक सत्र से तीसरी और छठी कक्षा में नई पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। इसकी तैयारी हो चुकी है। तीसरी कक्षा की चार पुस्तकें जारी हो गई हैं। छठी कक्षा की पुस्तकें भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। 15 मई तक सभी नई पुस्तकें छपकर आ जाएंगी। इससे पहले स्कूलों को ब्रिज कोर्स पढ़ाने को कहा गया है। अभिभावक से अनुरोध है कि वह पुस्तकों को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं, न ही गलत किताबें खरीदें।'

निरस्त रहेगी सिंगरौली, सत्याग्रह और जननायक एक्सप्रेस, बढ़ेगी यात्रियों की परेशानी

परिवहन विशेष न्यूज

अगले कुछ दिनों तक दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें निरस्त रहेगी और कई के मार्ग में बदलाव किया गया है। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी क्योंकि नियमित ट्रेनों में भीड़ होने के कारण लोगों को कंफर्म टिकट लेने में परेशानी हो रही है। इस स्थिति में कंफर्म टिकट लेकर यात्रा की योजना बना रहे यात्रियों की अन्य विकल्प की तलाश करनी होगी।

नई दिल्ली। अलग-अलग रेलखंड पर संरक्षा व रेलवे के आधारभूत ढांचा को मजबूत करने का काम चल रहा है। इस कारण ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो रही है। अगले कुछ दिनों तक दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें निरस्त रहेगी और कई के मार्ग में बदलाव किया गया है।

इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि नियमित ट्रेनों में भीड़ होने के कारण लोगों को कंफर्म टिकट लेने में परेशानी हो रही है। इस स्थिति में कंफर्म टिकट लेकर यात्रा की योजना बना रहे यात्रियों की अन्य विकल्प की तलाश करनी होगी।

निरस्त की गई ट्रेनें

सिंगरौली-हजरत निजामुद्दीन (22167) -14 अप्रैल और 21 अप्रैल

हजरत निजामुद्दीन-सिंगरौली (22168) – 15 अप्रैल 22 अप्रैल

रक्सौल-आनंद विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस (15273) - 15 अप्रैल

आनंद विहार -रक्सौल सत्याग्रह एक्सप्रेस (15274) - 14 अप्रैल

दरभंगा- अमृतसर जननायक एक्सप्रेस (15211)- 14 अप्रैल और 15 अप्रैल

अमृतसर-दरभंगा जननायक एक्सप्रेस (15212) -15 अप्रैल और 16 अप्रैल

इन ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है-

बरौनी-नई दिल्ली विशेष (02563/02564)

दरभंगा-नई दिल्ली विशेष (02569/02570)

नाहरालागुन-आनंद विहार टर्मिनल अरुणाचल एक्सप्रेस

पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस

सहरसा-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस

कामख्या-श्री माता वैष्णो देवी कटरा साप्ताहिक एक्सप्रेस

दरभंगा-नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस

मुजफ्फरपुर-आनंद विहार सप्त क्रांति एक्सप्रेस

आनंद विहार-सहरसा एक्सप्रेस

जयनगर-अमृतसर शहीद एक्सप्रेस

नोट- इन ट्रेनों के मार्ग में 14 से 16 अप्रैल तक बदलाव किया गया है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com

(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। **Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**